कृषि | विश्लेषण | जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

कार्तिक–मार्गशीर्ष 2080, दिसंबर 2023

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

बैठकें

सचित्र झलक

कन्नूर, केरल

राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्म जयंती कार्यक्रम

मुरादाबाद, उ.प्र.

स्वदेशी संघर्ष यात्राएं

जमशेदपुर, झारखंड

गदवा, झारखंड

गया, बिहार

गोड्डा, झारखंड

स्वदेशी पत्रिका

अ नु क्र म

वर्ष–31, अंक–12
कार्तिक–मार्गशीर्ष 2080 दिसंबर 2023

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–08

चीन की बढ़ती मुसीबतें

के.के श्रीवास्तव

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

06 **स्वदेशी**
एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ..... नरेंद्र मोदी

10 **आर्थिकी**
भारत के निर्यातों की बढ़ती लोकप्रियता ..... डॉ. अश्वनी महाजन

12 **आजकल**
उत्तराखंड स्थित सिल्कियारा की सुरंग के सबक ..... अनिल तिवारी

14 **शिक्षा**
उच्च शिक्षा; नये आयात ..... डॉ. जया कक्कड

16 **पर्यावरण**
कॉप–28: पर्यावरण और लोगों की जान बचाने के लिए छोड़ना होगा पेट्रोलियम उपयोग ..... विक्रम उपाध्याय

18 **विमर्श**
बबादी का दूसरा नाम है मुफ्तखोरी ..... स्वदेशी संवाद

20 **मुद्दा**
आतंक के रक्तबीज हमास के इज़राएल पर आक्रमण की पृष्ठभूमि ..... विनोद जौहरी

23 **अर्थ**
तेज गति से बढ़ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार ..... प्रहलाद सबनानी

26 **खेती–बारी**
बेहतर प्रोत्साहन नीति में संकट का समाधान ..... देविन्दर शर्मा

28 **व्यक्तित्व**
विवेकानंद के विचार आज भी प्रासंगिक ..... डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

30 **जल प्रबंधन**
नलकूपों से भी बढ़ रहा है जल संकट ..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

32 **बैंकिंग**
रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में कटौती के बारे में सोचना चाहिए ..... स्वदेशी संवाद

34 **विश्लेषण**
कुदरत से खिलवाड़ के फलितार्थ ..... शिवनंदन लाल

पाठकनामा

समस्या नहीं, संकट बनता प्रदूषण

जब कोई समस्या बढ़कर संकट में बदलने वाली हो तो उसका सामना करने और उसे रोकने के लिए सरकार और समाज दोनों को हर स्तर पर सक्रिय होना चाहिए। मगर इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि दिल्ली, जो कि देश की राजधानी भी है, में प्रदूषण के चरम स्थिति में पहुंचने के बावजूद न तो आम आदमी पार्टी की सरकार को पर्याप्त सक्रियता बरतने की जरूरत महसूस हुई और न यहां के निवासियों को इस बात की फिक्र हुई कि इसका खामियाजा घूम फिर कर उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। हालात ऐसे हैं कि घर से बाहर निकलना भी जोखिम भरा हो गया है। दीपावली के पहले बारिश के कारण मौसम में थोड़ी राहत हुई थी, आसमां भी साफ हो गया था और वायु गुणवत्ता में भी सुधार आया था। लेकिन दीपावली के बाद लोगों ने जानबूझकर आतिशबाजी के बहाने नियंत्रित हुई स्थिति को फिर से अनियंत्रित कर दिया। मतलब साफ है कि प्रदूषण जैसे मसले पर जागरूकता का घोर अभाव है। सरकार तो उदासीन है ही, आम लोग भी समस्या का हल खोजने की वजह समस्या को और अधिक बढ़ाने में जुटे हुए हैं।

बड़ा सवाल यह है कि सरकारी संकट का हल खोजने के क्रम में कुछ औपचारिक उपाय से आगे क्यों नहीं बढ़ पाती। दिल्ली में प्रदूषण की जो धुंध छाई रहती है और हवा में पीएम 2.5 जैसे सूक्ष्म कणों की मौजूदगी है, इसकी वजह वाहनों के धुएं से लेकर पराली तक को माना जा रहा है। मगर ऐसा क्यों है कि हवा के दबाव की स्थिति को देखते हुए प्रदूषण को संकट में बदलने वाले वास्तविक मर्म की पहचान करके उसे कुछ दिनों के लिए रोका क्यों नहीं जाता। दिल्ली में प्रदूषण एक गंभीर संकट के रूप में उपस्थित है। सवाल है कि दिल्ली की सरकार और यहां के भद्र नागरिक सभी स्तरों पर संवेदनशीलता के साथ आगे कब आएंगे?

डॉ. पराक्रम सिंह, *शालीमार बाग दिल्ली*

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत की सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा आवश्यक है। हम 'वसुधैव कुटुंबकम' की परंपरा का पालन करते हैं, लेकिन हमारी सेनाएं देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी बाहरी या आंतरिक स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं।

द्रोपदी मुर्मू, महामहिम, भारत

भारत की युवा शक्ति की उल्लेखनीय उपलब्धि से प्रभावित हूं जो हमारे राष्ट्र में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

घटते विनिर्माण ने बेरोजगारी की समस्या को जन्म दिया। इस प्रकार, पिछले चार वर्षों में अमेरिका में चीन के निर्यात में गिरावट, और भारत के निर्यात में वृद्धि, भारतीय विनिर्माण के लिए अच्छी खबर है। यह दर्शाता है कि भारतीय उत्पाद, चीन की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो गए हैं।

डॉ. अश्वनी महाजन
राष्ट्रीय सहसयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

2026 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी

30 नवंबर 2023 को भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023–24 की दूसरी तिमाही, जुलाई से सितंबर के दौरान भारत की जीडीपी 7.6 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ी, जो 2022–23 की दूसरी छमाही की संवृद्धि दर 6.2 प्रतिशत से कहीं ज्यादा रही। गौरतलब है कि इस तिमाही में भारत की चालू कीमतों पर जीडीपी 71.66 लाख करोड़ रही, जिसका मतलब यह है कि भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय इस तिमाही में 2.01 लाख रूपए तक पहुंच चुकी है। सितंबर माह में डॉलर की औसत बाजार कीमत 82.5 रूपये प्रति डालर के हिसाब से आज भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 2436 डॉलर प्रतिवर्ष है। यदि जीडीपी की अर्ध–वार्षिक ग्रोथ के आँकड़े देखें तो 2023–24 मार्च से सितंबर की जीडीपी 2022–23 के वर्ष के पूर्वार्ध की तुलना में ग्रोथ 7. 7 प्रतिशत रिकॉर्ड की गयी। यदि जीडीपी ग्रोथ की यह रफ़्तार जारी रहती है तो जनसंख्या की अनुमानित वृद्धि के साथ सितंबर 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 3600 अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष पहुँच सकती है। ग़ौरतलब है कि वर्ष 2014 में यह मात्र 1500 अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष ही थी।

भारत में जीडीपी की संवृद्धि में हालांकि सभी क्षेत्रों का योगदान रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तिमाही की मूल्य संवृद्धि में ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का रहा है, यानि 13.9 प्रतिशत। ग्रोथ की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रोथ का क्षेत्र कंस्ट्रक्शन का रहा है, जहां 13.3 प्रतिशत की दर से संवृद्धि देखी गई है। तीसरा क्षेत्र बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवा का है, जहां 10.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की गई है। देखा जाए तो सेवा क्षेत्र में ग्रोथ बहुत उल्लेखनीय नहीं है। चिंता का विषय यह है कि इस तिमाही में कृषि क्षेत्र में भी ग्रोथ बहुत कम 1.2 प्रतिशत दर्ज की गई है। लेकिन यह किसी मौलिक दोष के कारण नहीं, बल्कि मानसून की कमी के कारण है। मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत की नीति की सफलता की ओर इंगित करती है। बड़ी संख्या में नई उत्पादन इकाईयां हर क्षेत्र में लग रही हैं। इनमें इलैक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम, मशीनरी, सोलर, प्रतिरक्षा, कैमिकल, खिलौने, वस्त्र सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल हैं। भारत सरकार की उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन की नीति के कारण अब जल्द ही लैपटॉप, सेमीकंडक्टर इत्यादि का उत्पादन भी शुरू हो सकता है। यदि कुछ खास संकेतकों को देखा जाए तो कोयला, स्टील, सीमेंट, खनन, बिजली उत्पादन इत्यादि में भी खासी संवृद्धि दर दिखाई दे रही है। कोयले के उत्पादन में 16. 3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है, तो सीमेंट उत्पादन में 10.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है। स्टील उत्पादन में 19.5 प्रतिशत वृद्धि दिखाई दे रही है। खनन में भी 11.5 प्रतिशत संवृद्धि एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। हवाई यात्रियों की संख्या में 22.7 प्रतिशत वृद्धि हुई है। बैंकों में जमा भी 11.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, जबकि बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों में 13 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज हुई है। ये सभी आंकड़े देश में बेहतर होते आर्थिक वातावरण की ओर इंगित कर रहे हैं। समझना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ का सीधा असर रोजगार पर पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार की संभावनाएं सेवा क्षेत्र से कहीं ज्यादा होती है।

भारत में जहां आर्थिक संवृद्धि की दर 7.6 प्रतिशत है, चीन में यह मात्र 4.9 प्रतिशत दर्ज की गई है, रूस में 5.5 प्रतिशत और संयुक्त राज्य अमरीका में यह 5.2 प्रतिशत। गौरतलब है कि जर्मनी जो इस समय जीडीपी की दृष्टि से भारत से एक स्थान ऊपर है, वहां जीडीपी में 0.4 प्रतिशत की दर से गिरावट दर्ज की जा रही है। यदि जीडीपी में वर्तमान दर से वृद्धि होती है तो भारत की वार्षिक जीडीपी डॉलरों में 3.5 खरब डॉलर पहुंच जाएगी, और जर्मनी की वर्तमान जीडीपी 4.1 खरब डॉलर में यदि अनुमानों के अनुसार 0.4 प्रतिशत की कमी दर्ज होती है तो भारत की जीडीपी की तुलना में जर्मनी की जीडीपी (4.08 खरब डालर) से मात्र 600 अरब डालर ही कम रह जायेगी। यदि विकास की वर्तमान दर कायम रहती है, तो भारत ढाई साल से भी कम समय में जर्मनी की जीडीपी को पार कर सकता है। हमारे ग्रोथ का अनुभव कुछ खट्टा मीठा रहा है। पिछले तीन दशको में जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े तो उत्साहजनक रहे लेकिन रोज़गार के मोर्चे पर हम पिछड़ते रहे। उसका कारण यह रहा कि हमारी जीडीपी ग्रोथ में सेवाओं का योगदान ज़्यादा, लेकिन मैन्यूफ़ैक्चरिंग का योगदान कहीं कम रहा। देखा जाए तो 1995–96 में जहां जीडीपी में मैन्यूफ़ैक्चरिंग का योगदान 21.5 प्रतिशत था, वह 2017–18 तक घटकर मात्र 16.5 प्रतिशत ही रह गया। मैन्यूफ़ैक्चरिंग में जहाँ रोज़गार की संभावनाएं सेवा क्षेत्र से कई गुना ज़्यादा होती है, का हिस्सा जीडीपी में घटने का असर रोज़गार वृद्धि पर भी पड़ा। युवा भारत की जनसांख्यिकी का फ़ायदा मिलने की बजाए देश में युवा जनसंख्या को रोज़गार न मिलने के कारण समस्याएँ और ख़तरे बढ़ने लगे। ग़ौरतलब है कि देश में बेरोज़गारी की दर लगातार बढ़ती रही। कोविड 19 के प्रकोप के बाद यह समस्या पहले से ज़्यादा विकट हो गई थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैन्यूफ़ैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के कारण इस क्षेत्र में कुछ ग्रोथ दिखाई देने लगी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी की दर में जुलाई–सितंबर 2022 में 7.7 प्रतिशत से घटती हुई जुलाई–सितंबर 2023 में 6.6 प्रतिशत ही रह गई है।

एक उज्ज्वल भविष्य की ओर

भारत द्वारा जी–20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के आज एक वर्ष से अधिक हो गए। यह वसुधैव कुटुंबकम, 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' की भावना को प्रतिबिंबित करने, इसके लिए पुनः प्रतिबद्ध होने और इसे जीवंत बनाने का क्षण है। जब पिछले वर्ष भारत को यह जिम्मेदारी मिली थी, तब विश्व विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा था। कोविड–19 महामारी, बढ़ते जलवायु खतरे, वित्तीय अस्थिरता व विकासशील देशों में ऋण संकट जैसी चुनौतियां सामने थीं। कमजोर होता बहुपक्षवाद इन चुनौतियों को और गंभीर बना रहा था। प्रतिस्पर्धा के बीच विभिन्न देशों में परस्पर सहयोग की भावना में कमी आ गई और इसका प्रभाव वैश्विक प्रगति पर पड़ा।

जी–20 का अध्यक्ष बनने के बाद भारत ने दुनिया के सामने जीडीपी–केंद्रित सोच से आगे बढ़कर मानव केंद्रित प्रगति का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। दुनिया को याद दिलाने का प्रयास किया कि कौन सी चीजें हमें जोड़ती हैं। अंततः भारत के प्रयासों का परिणाम आया, वैश्विक संवाद आगे बढ़ा और कुछ देशों के सीमित हितों के ऊपर कई देशों की आकांक्षाओं को महत्व दिया गया। इसके लिए बहुपक्षवाद में मूलभूत सुधार की जरूरत थी। 'समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई–उन्मुख और निर्णायक', ये चार शब्द जी–20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं। नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, जिसे सभी जी–20 सदस्यों द्वारा अपनाया गया है, इन सिद्धांतों पर कार्य करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

समावेश की भावना हमारी अध्यक्षता के केंद्र में रही। जी–20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने से 55 अफ्रीकी देशों को जगह मिली, जिससे जी–20 का विस्तार वैश्विक आबादी के 80 प्रतिशत तक पहुंच गया। भारत द्वारा अपनी तरह की पहली बैठक 'वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट' ने बहुपक्षवाद की नई शुरुआत की। इस बैठक के दो संस्करण आयोजित हुए। भारत ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं को मुख्यधारा में लाने में सफल रहा। इससे एक ऐसे युग की शुरुआत हुई है, जहां विकासशील देशों को ग्लोबल नैरेटिव की दिशा तय करने का अवसर प्राप्त होगा।

जी–20 का अध्यक्ष बनने के बाद भारत ने दुनिया के सामने जीडीपी–केंद्रित सोच से आगे बढ़कर मानव केंद्रित प्रगति का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। दुनिया को याद दिलाने का प्रयास किया कि कौन सी चीजें हमें जोड़ती हैं।
– नरेंद्र मोदी

जी–20 में भारत के घरेलू दृष्टिकोण का भी प्रभाव दिखा। इस आयोजन ने लोक अध्यक्षता का रूप ले लिया, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की दृष्टि से सही था। जन–भागीदारी कार्यक्रमों के जरिये जी–20 विश्व के 1.4 अरब नागरिकों तक पहुंचा और सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को भागीदार के रूप में शामिल किया गया। भारत ने सुनिश्चित किया कि मुख्य विषयों पर विश्व का ध्यान जी–20 के दायित्वों के अनुरूप विकास के व्यापक लक्ष्यों की ओर हो।

2030 के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए भारत ने सतत विकास लक्ष्य में तेजी लाने के लिए जी–20 का 2023 एक्शन प्लान पेश किया। इसके लिए भारत ने स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, पर्यावरणीय स्थिरता सहित परस्पर जुड़े मुद्दों पर व्यापक कार्रवाई–उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया। इस प्रगति को संचालित करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस मामले में आधार, यूपीआई और डिजिलॉकर जैसे डिजिटल नवाचार के क्रांतिकारी प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने वाले भारत ने निर्णायक सिफारिशें कीं। कुल 16 देशों के 50 से अधिक डीपीआई को शामिल करने वाली रिपॉजिटरी, समावेशी विकास की शक्ति का लाभ उठाने के लिए ग्लोबल साउथ को डीपीआई का निर्माण करने, उसे अपनाने और व्यापक बनाने में मदद करेगी।

एक पृथ्वी की भावना के तहत हमने स्थायी और न्यायसंगत बदलाव लाने के महत्वाकांक्षी एवं समावेशी लक्ष्य पेश किए। घोषणा का 'ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट' एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करके भुखमरी से निपटने और पृथ्वी की रक्षा के बीच चुनाव करने की चुनौतियों का समाधान करता है। इस रोडमैप में रोजगार एवं इकोसिस्टम

जन–भागीदारी कार्यक्रमों के जरिये जी–20 विश्व के 1.4 अरब नागरिकों तक पहुंचा और सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को भागीदार के रूप में शामिल किया गया। भारत ने सुनिश्चित किया कि मुख्य विषयों पर विश्व का ध्यान जी–20 के दायित्वों के अनुरूप विकास के व्यापक लक्ष्यों की ओर हो।

एक–दूसरे के पूरक हैं, उपभोग जलवायु बदलाव के प्रति सचेत है और उत्पादन पृथ्वी के अनुकूल है। साथ ही, जी–20 घोषणा में 2030 तक अक्षय ऊर्जा की वैश्विक क्षमता को तीन गुना करने का आह्वान किया गया है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की स्थापना और ग्रीन हाइड्रोजन अपनाने की दिशा में ठोस प्रयास के साथ स्वच्छ एवं हरित दुनिया बनाने संबंधी जी–20 की महत्वाकांक्षाएं निर्विवाद हैं। यह हमेशा से भारत का मूल्य रहा है और सतत विकास के लिए, जीवनशैली के माध्यम से, दुनिया हमारी सदियों पुरानी परंपराओं से लाभान्वित हो सकती है।

इसके अलावा घोषणापत्र में ग्लोबल नॉर्थ से पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी मदद का अनुरोध किया गया है। पहली बार विकास के वित्त–पोषण से जुड़ी राशि में भारी बढ़ोतरी की जरूरत को स्वीकारा गया, जो अरबों से बढ़कर खरबों डॉलर हो गई है। जी–20 ने माना कि विकासशील देशों को 2030 तक अपने 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' को पूरा करने के लिए 5.9 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है। इतने ज्यादा संसाधन की जरूरत को देखते हुए जी–20 ने बेहतर, विशाल और प्रभावकारी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक के महत्व पर विशेष जोर दिया। साथ ही, भारत संयुक्त राष्ट्र में सुधार, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद जैसे प्रमुख संस्थानों के पुनर्गठन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिससे और न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

नई दिल्ली घोषणापत्र में महिला–पुरुष समानता को केंद्र में रखा गया, जिसकी परिणति अगले वर्ष महिलाओं के सशक्तीकरण पर एक विशेष कार्य समूह के गठन के रूप में होगी। भारत का महिला आरक्षण विधेयक 2023 महिलाओं के नेतृत्व में विकास के प्रति हमारी वचनबद्धता का प्रतीक है। नई दिल्ली घोषणापत्र इन प्रमुख प्राथमिकताओं में सहयोग सुनिश्चित करने की नई भावना का प्रतीक है। बड़े गर्व की बात है कि हमारी अध्यक्षता में जी–20 ने 87 परिणाम हासिल किए और 118 दस्तावेज अपनाए, जो अतीत की तुलना में बहुत अधिक है। आतंकवाद व नागरिकों की हत्या पूरी तरह अस्वीकार्य है और हमें शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाकर इससे निपटना चाहिए। शत्रुता से परे जाकर मानवतावाद को अपनाना होगा और दोहराना होगा कि यह युद्ध का युग नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी अध्यक्षता में भारत ने असाधारण उपलब्धियां हासिल कीं : बहुपक्षवाद में नई जान फूंकी, ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद की, विकास की हिमायत की और हर जगह महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए लड़ाई लड़ी।

अब जब हम जी–20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंप रहे हैं, तब हम इस विश्वास के साथ ऐसा कर रहे हैं कि समस्त लोगों, पृथ्वी, शांति और समृद्धि के लिए हमारे सामूहिक कदमों की गूंज आने वाले वर्षों में निरंतर सुनाई देती रहेगी। ❑❑

https://www.livehindustan.com/blog/story-hindustan-opinion-column-30-november-2023-9004526.html

चीन की बढ़ती मुसीबतें

पश्चिम के निर्यातक देशों के मुंह में पानी ला देने वाली अर्थव्यवस्था के बावजूद चीन इन दिनों घरेलू स्तर पर जनसंख्यिकी, ऋण, सामाजिक अशांति, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच अस्थिर सहजीवी संबंध, विकास बनाम सामानता के मसलों पर, तो विश्व मंच पर तकनीकी प्रबंध, चीन प्लस वन की नीति, पश्चिमी दुनिया के साथ शीत युद्ध जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है।

पिछले चार दशकों के दौरान राष्ट्रों के समूह के बीच चीन राजनीतिक और आर्थिक रूप से अद्वितीय पैमाने पर विकास किया है। राज्य द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों और विवेकपूर्ण निर्णय ने चीन की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने और उसके दीर्घकालिक प्रगति में योगदान दिया है। हालांकि अब विकास की गति थोड़ी लड़खड़ा रही है तो दुनिया भर की निगाहें इस बात का अंदाजा लगाने में जुटी हुई है कि आय के जाल में चीन क्यों फंसता जा रहा है? प्रश्न यह भी उठ रहा है कि क्या चीन अपनी गति फिर से हासिल कर पाएगा? यदि हां, तो कैसे?

30 वर्षों से अधिक के समय तक चीनी मॉडल ने चीन में उच्च आर्थिक विकास, शहरीकरण और गरीबी में कमी लाने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन इस दौरान बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय गिरावट, भ्रष्टाचार, बढ़ती असमानताएं, भारी कर्ज का बोझ, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर नागरिक आवाज भी उठाते रहे हैं। हाल ही में कई स्थानों पर शांत विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। दरअसल चीन की अर्थव्यवस्था का यह पेंचोखम एक तरफ निर्यात अधिशेष पैदा करने तो दूसरी ओर पूंजी निर्माण के हित में घरेलू उपयोगकर्ताओं की खपत को जानबूझकर दबा देने से उभरा है। वर्ष 2007 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने कहा था कि इस नीति से अर्थव्यवस्था अस्थिर, असंतुलित, असंगठित हो गई है। तब चीन ने इस पर गंभीरता से ध्यान देने का फैसला भी किया था। उदाहरण के लिए चीन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया। व्यवस्था के मुताबिक यहां या तो कोई देश बुनियादी विज्ञान और मूलभूत प्रौद्योगिकियों में सफलता हासिल कर सकता है या दूसरे तरीके से यह मौजूदा प्रौद्योगिकियों को बेहतर अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित कर सकता है। चीन ने दूसरा रास्ता अपनाया और कथित तौर पर कभी–कभी दूसरे देश से तकनीक भी चुरा ली। इसी का परिणाम है कि 25 सबसे मूल्यवान प्रौद्योगिकी कंपनियों में से चीन आज 9 का मालिक है। हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे उभरते क्षेत्रों में खूब हाथ पांव मारे हैं, लेकिन चीन का नकारात्मक पक्ष यह रहा है कि उसने विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों, धन और मानव को तैनात किया है, लेकिन वैज्ञानिक, रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कभी भी किसी संस्थागत बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं किया है। जैसे कि वहां की शिक्षा प्रणाली ने छात्रों में मौलिक सोच पैदा करने की बजाय रटने की शिक्षा को बढ़ावा दिया है। इसी तरह अनुसंधान निकायों में बहुत अधिक स्वायत्तता का हमेशा अभाव रहा है। चीनी वैज्ञानिक कभी भी वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय का हिस्सा नहीं बने और भाईचारे के स्तर पर भी विचारों का कभी आदान–प्रदान नहीं किया। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यह साम्यवादी शासन के सामान्य रूप से दूसरी दुनिया और विशेष रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के प्रति अविश्वास के कारण भी हो सकता है।

दूसरी और इसकी बंद प्रणाली के कारण चीन का वित्तीय क्षेत्र (इक्विटी और बांड बाजार) अविकसित है। वित्तीय मध्यस्थों सहित बहुत कम स्वतंत्र बाजार के खिलाड़ी वहां

चीन एक तरफ घरेलू स्तर पर विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ विश्व मंच पर तकनीकी प्रतिबंध और पश्चिमी दुनिया के साथ शीत युद्ध की समस्याओं का सामना कर रहा है। भारत के लिए यह एक मौका जैसा है।

– के.के. श्रीवास्तव

हैं। यहां भी विदेशी संस्थानों पर अत्यधिक अविश्वास किया जाता है। लेकिन इसके दो झटके लगे, एक– चीन एक जीवंत और अच्छी तरह से विनियमित शेयर बाजार के माध्यम से अपने विकास के लिए धन जुटाना में सक्षम नहीं है और दो– भले ही चीन विश्व व्यापार में काफी महत्व रखता है लेकिन इसकी मुद्रा पर्याप्त कठोर नहीं है। यह विश्व व्यापार और वाणिज्य मंच पर कोई अनुपातिक भूमिका नहीं निभाता है। वित्तीय प्रणाली की यह कमजोरी फिर से कम्युनिस्ट पार्टी के खुले बाजार प्रणाली के प्रति अविश्वास से उत्पन्न होती है जो संभवत एक ओर संभावित अशांति का कारण बन सकती है तो दूसरी ओर सिस्टम पर पार्टी की पकड़ को भी खो सकती है। हालांकि कोई भी निजी क्षेत्र के प्रति पार्टी के विश्वास आदि के अन्य उदाहरण दे सकता है लेकिन मूल विचार स्पष्ट है अब समय आ गया है कि पार्टी राजनीतिक शक्ति के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले अवसरों और इसमें शामिल जोखिमों का आकलन करें। विरोधाभासी रूप से यह प्रणाली विश्वास व्यवस्था और राजनीति पर हावी होना चाहती है पर एक सीमा के बाद वैश्विक व्यवस्था के साथ एकीकृत होने की मंशा नहीं रखती।

इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन विश्व मंच पर एक बहुत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला खिलाड़ी है और शायद इसीलिए इसकी समस्याएं एक अकेली नहीं है। ऐसे में चीन चाह कर भी 180 डिग्री का मोड़ नहीं ले सकता और न ही उसे पश्चिमी आर्थिक विकास मॉडल के साथ काम करने से उसका हित सधेगा, चीन को रुकने और एक नई प्ले बुक डिजाइन करने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि वैश्विक गांव की अवधारणा को अब धीरे–धीरे त्याग दिया जा रहा है। भारत सहित दुनिया के कई देश अपनी औद्योगिक नीतियों में आत्मनिर्भरता को फिर से डिजाइन कर रहे हैं और बाजारों के मुक्त खेल पर आर्थिक नियंत्रण को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह सब उनके विषयों के कल्याण को सुनिश्चित करने और लक्षित गति से आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए है।

भू राजनीतिक उथल–पुथल के बीच (रूस यूक्रेन युद्ध, इसराइल हमास संघर्ष) जलवायु परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के आने के बाद समाजवाद/साम्यवाद की ओर वापसी अब न तो संभव है और नहीं वांछनीय ही। ऐसे में चीन को दुनिया को यह समझाने की जरूरत है कि वह आर्थिक राजनीतिक या अन्य तरह से आधिपत्य जमा कर अन्य देशों के लिए कोई खतरा नहीं है। यह ठीक है कि चीन वैश्विक नेतृत्व की छवि हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा को कभी छुपाता नहीं है लेकिन बूढ़े होते चीन को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत कम वास्तविक मजदूरी पर श्रम बल की तीव्र आपूर्ति अब पहले की तरह उपलब्ध नहीं होगी। पूर्व की तरह आगे चीन की विकास दर 8 से 10 प्रतिशत के आसपास नहीं होगी। इसके माध्यम आय के जाल में फंसने की संभावना अधिक है। समस्याओं को और बढ़ाने के लिए स्थानीय सरकारी ऋण और कारपोरेट ऋण दोनों मौजूद हैं जो वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास दोनों पर एक साथ प्रतिकूल प्रभाव छोड़ते हैं।

लेकिन यह मसला केवल घरेलू स्तर पर चीनी अर्थव्यवस्था की गति खोने तक ही सीमित नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका सहित कई अन्य देश खुलेआम चीन के साथ शत्रुतापूर्ण हो रहे हैं। इसका एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण पश्चिमी विश्व द्वारा अपनाई गई चीन प्लस वन नीति है दूसरा है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में असहयोग। उदाहरण के लिए वर्ष 2018 के दौरान वालमार्ट का 80 प्रतिशत शिपमेंट चीन से आया, लेकिन जनवरी–अगस्त 2023 की अवधि के लिए यह आंकड़ा घटकर केवल 60 प्रतिशत रह गया है। वॉलमार्ट और अन्य पश्चिमी कंपनियों का चीन से दूर जाना एक ओर बढ़ते राजनीतिक तनाव तो दूसरी ओर चीन से बढ़ती आयात लागत के कारण भी है। हालांकि भारत की तरह अमेरिका भी अंतिम माल और आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्था के हिस्से के रूप में चीन से एक महत्वपूर्ण आयातक देश बना हुआ है, क्योंकि फ्रेंड सॉरिंग आयात के सस्ते स्त्रोत का कोई विकल्प नहीं है।

फिर भी अमेरिका चीन को निशाने पर रखे हुए हैं। अमेरिका अर्ध चालकों और उच्च तकनीक बौद्धिक संपदा तक चीन की पहुंच को काफी हद तक प्रतिबंधित करना चाहता है। यदि इसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया तो यह चीन की तकनीकी प्रगति में बाधा ही खड़ा करेगा। चीन भी होशियारी से चिप बनाने में उपयोगी खनिजों की आपूर्ति तक पहुंच हासिल करने की कोशिश कर रहा है।

कुल मिलाकर चीन एक तरफ घरेलू स्तर पर विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ विश्व मंच पर तकनीकी प्रतिबंध और पश्चिमी दुनिया के साथ शीत युद्ध की समस्याओं का सामना कर रहा है। भारत के लिए यह एक मौका जैसा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी दुनिया चीन से अलग हो सकती है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी होगी कि चीन एक कम से कम लागत वाला निर्यातक देश है। चीन की अर्थव्यवस्था पश्चिमी निर्यातकों के लिए मुंह में पानी ला देने वाली अर्थव्यवस्था है। इसलिए भारत को अपना आर्थिक लक्ष्य हासिल करने के लिए सावधानी से चलने की जरूरत है। ❑❑

भारत के निर्यातों की बढ़ती लोकप्रियता

हाल ही में एक वैश्विक सलाहकार फर्म वॉस्टन कंस्लटिंग ग्रुप ने शोध में यह बताया है कि 2018 से लेकर 2022 तक अमरीका को भारत के निर्यात 44 प्रतिशत बढ़े हैं, जबकि चीन से अमरीका को निर्यात 10 प्रतिशत घट गए हैं। हालांकि अमरीका के मैक्सिको व आसियान देशों से भी आयात बढ़े है, महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय उत्पाद चीनी उत्पादों को प्रतिस्थापित करते हुए अमरीकी बाजारों में अपनी पैठ बना रहे हैं। भारतीय निर्यातों में यह वृद्धि मशीनरी से लेकर खाद्य पदार्थों, स्वास्थ्य एवं आरोग्य उत्पादों, कपड़े, जुते, खिलौनों समेत विभिन्न उत्पादों में दिखाई देती है। रिटेल चेन वालमार्ट का अकेले ही लक्ष्य है कि वह भारत से 2027 तक 10 अरब डालर का सामान हर साल खरीदेगा।

इस शताब्दी के प्रारंभ से ही चीन ने लगातार दुनिया के बाजारों में अपनी पैठ बनाई है। गौरतलब है कि चीन के दुनिया भर में कुल निर्यात वर्ष 2000 में 253 अरब अमरीकी डालर से बढ़ते हुए वर्ष 2020 तक 3730 अरब अमरीकी डालर तक पहुंच गये थे। अकेले भारत में ही चीन के निर्यात वर्ष 2000 में 1.47 अरब अमरीकी डालर से बढ़ते हुए वर्ष 2020 तक 102 अरब अमरीकी डालर पहुंच गये थे। इस दौरान अमरीका में चीन के निर्यात 100 अरब अमरीकी डालर से बढ़ते हुए 536.3 अरब डालर तक पहुंच गये। चीन से बढ़ते आयातों से भारत को बड़ा नुकसान हुआ और हमारी कुल जीडीपी में मैन्युफेक्चिरिंग का योगदान वर्ष 1995–96 में लगभग 21.3 प्रतिशत से घटता हुआ वर्ष 2018–19 तक 16.3 प्रतिशत तक पहुंच गया। इसी प्रकार से दुनिया भर में मैन्युफेक्चिरिंग का ह्रास हुआ और इसका सीधा लाभ चीन को मिला।

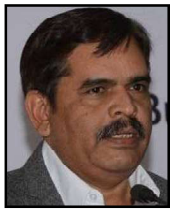

भारतीय रूपया क्रय शक्ति के आधार पर डालर की बाजार कीमत से लगभग 4 गुना ज्यादा मूल्यवान है। यानि हमारी प्रतिस्पर्द्धी लागत दुनिया से और अधिक कम हो सकती है। इसलिए भारत से निर्यात बढ़ने की खासी अच्छी संभावनाएं है लेकिन उसके लिए सरकार को सतत् प्रयास करने होंगे।
– डॉ. अश्वनी महाजन

घटती मैन्युफेक्चिरिंग ने शेष दुनिया के मुल्कों में बेरोजगारी की समस्या को जन्म दिया। पिछले चार वर्षों में पहली बार अमरीका में चीन के निर्यातों में कमी और भारत द्वारा अमरीका को निर्यातों में वृद्धि भारतीय मैन्युफेक्चिरिंग के लिए एक अच्छी खबर है।

चीन से अधिक प्रतिस्पर्द्धी हुए भारतीय उत्पाद

यह बात सही है कि अमरीकी सरकार ने चीन से आयात कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किये हैं, जिनमें आयात शुल्क में वृद्धि भी शामिल है। लेकिन साथ ही साथ अमरीकी सरकार ने भारत से भी आयातों को कम करने के लिए, पूर्व में दी गई रियायतों को वापिस तो लिया ही, साथ ही साथ आयात शुल्कों में भी वृद्धि की है। गौरतलब है कि विश्व व्यापार संगठन समझौते के अंतर्गत अमरीका एकमात्र ऐसा देश है जो किसी एक या अधिक देशों पर अलग आयात शुल्क लगा सकता है।

लेकिन तमाम अमरीकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत से अमरीका को निर्यात 44 प्रतिशत बढ़ना विशेष महत्व रखता है। बॉस्टन कंसेल्टिंग ग्रुप का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारत का सामान अमरीका में, अमरीकी लागत के अपेक्षा 15 प्रतिशत सस्ता पड़ता

है, जबकि चीन का सामान अमरीकी सामान की तुलना में मात्र 4 प्रतिशत ही सस्ता है। इसीलिए अमरीकी बाजार भारत में निर्मित सामानों को चीनी सामानों की अपेक्षा अर्हता देते है। समझना होगा कि जहां अमरीका भी मैन्युफेक्चिरिंग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है, उसके बावजूद भारतीय उत्पाद की जबरदस्त प्रतिस्पर्द्धी शक्ति इस बात का द्योतक है कि पूरी दुनिया में भारतीय, खासतौर पर विकसित देशों में भारत के साजो–सामान के बाजार का विस्तार होने की पूरी संभावना है। यह बात सर्वविदित ही है कि आज के प्रतियोगी युग के बाजार में लागत प्रतिस्पर्द्धा की एक बड़ी भूमिका है।

2000 अरब डॉलर निर्यात का लक्ष्य

मार्च 31, 2023 को भारत सरकार द्वारा नई विदेश व्यापार नीति घोषित की गई थी। इस नीति में वर्ष 2030 तक भारत से कुल वस्तुओं सेवाओं के निर्यात का लक्ष्य 2 खरब डालर यानि 2000 अरब डालर का रखा गया है। गौरतलब है कि बीते वर्ष 2022–23 में भारत के कुल निर्यात 770 अरब डालर रहे, वर्ष 2030 तक इन निर्यातों को 2000 अरब डालर तक बढ़ाना एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। जबकि पिछले 10 सालों में निर्यातों के बढ़ने की गति अत्यंत धीमी रही है, इसलिए यह चुनौती और भी बड़ी दिखाई देती है। लेकिन पिछले साल 2022–23 में वस्तु एवं सेवाओं के निर्यातों में 11. 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसलिए यदि इस वृद्धि दर को 14.81 प्रतिशत तक ले जाया जाये तो वर्ष 2030 तक 2000 अरब डालर के निर्यातों के लक्ष्य तक पहुंचना कोई कठिन बात दिखाई नहीं देती।

कैसे बढ़ेंगे देश से निर्यात

सबसे पहले तो निर्यात बढ़ाने के लिए जरूरी है कि देश में उत्पादन और जीडीपी बढ़े। गौरतलब है कि 2013–14 में भारत की कुल जीडीपी 2 खरब डालर यानि 2000 अरब डालर की थी। उस समय देश के कुल निर्यात 500 अरब डालर से थोड़ा कम थे। 2022–23 में जब भारत की जीडीपी 3.5 खरब डालर की रही, भारत के निर्यात 770 अरब डालर के रहे और 2030 में यदि लक्ष्य के अनुरूप भारत की जीडीपी का 7 खरब डालर हो जाती है तो देश का कुल निर्यात 2 खरब डालर होना असंभव नहीं है।

भारत के कृषि निर्यात, 2021–22 में ही 50.3 अरब डालर पहुँच गये थे। 2022–23 में ये निर्यात 53.3 अरब डालर पहुंच गये हैं। दुनिया में खाद्य पदार्थों में कमी और भारत में खाद्य पदार्थों का अतिरेक, देश से खाद्य निर्यातों में वृद्धि की ओर इंगित करता है। पिछले एक–दो वर्षों में भारत दुनिया भर के कई मुल्कों को खाद्य पदार्थ निर्यात करते हुए, दुनिया के कई मुल्कों को भूख से मुक्तिदाता के रूप में स्थापित हुआ है।

आज भारत अपनी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं की 68 प्रतिशत आपूर्ति देश से ही करता है। यही नहीं हमारे प्रतिरक्षा निर्यात 2016–17 में मात्र 1521 करोड़ रूपये ही थे, जो 2022–23 तक ये दस गुणा से ज्यादा बढ़कर 15920 करोड़ रूपये तक पहुंच गये हैं। भविष्य में प्रतिरक्षा निर्यातों में बड़ी वृद्धि अपेक्षित है।

खिलौनों के निर्यात में 2018–19 और 2022–23 के बीच 60 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। गौरतलब है कि खिलौनों सहित विभिन्न प्रकार के उत्पादों जैसे सोलर पैनल, वस्त्र, मशीनरी उत्पाद, प्रतिरक्षा के साजोसामान, इलैक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, मोबाईल फोन और लैपटॉप इत्यादि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीएलआई के नाम से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन सब का उत्पादन बढ़ने से निर्यातों, खासतौर पर मोबाईल फोन, मशीनरी, सोलर पैनल, इलैक्ट्रॉनिक्स के सामान और टेलीकॉम इत्यादि के निर्यात बढ़ रहे हैं। लगातार विकसित होता भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र भी निर्यात की असीम संभावनाएं प्रस्तुत कर रहा है।

बॉस्टन कंस्लटिंग ग्रुप की शोध से यह बात स्पष्ट हो रही है कि अमरीका में जो भारत के निर्यात बढ़े है और वालमार्ट सरीखे रिटेल चेन भी अब भारत की ओर रूख कर रहे हैं, यह अमरीका के भारत के प्रति किसी प्रेम के कारण नहीं, बल्कि हमारे उत्पादों की प्रतिस्पर्द्धी ताकत के बलबूते हो रहा है। प्रतिस्पर्द्धी ताकत को बढ़ाने में पीएलआई योजना का तो योगदान है ही, देश में बढ़ती उत्पादन क्षमता के कारण पैमाने की बचतों के कारण भी लागत कम हो रही है। साथ ही साथ देश में लॉजिस्टक लागत को कम करने हेतु डिजिटलीकरण का विशेष योगदान है। यही नहीं देश में सड़कों, घरेलू जल यातायात, समुद्री बंदरगाहों सहित विभिन्न प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से माल ढुलाई और यातायात की लागत कम हो रही है। यह बात तो सर्वथा सिद्ध है कि भारत में मजदूरी लागत चीन समेत कई मुल्कों से काफी कम है।

हमें समझना होगा कि हालांकि अमरीकी डालर की बाजार कीमत के आधार पर 2022–23 में हमारी जीडीपी 3.5 खरब डालर ही थी, लेकिन क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर हमारी जीडीपी 13 खरब डालर की थी, यानि लगभग 4 गुना ज्यादा। इसका मतलब यह है कि भारतीय रूपया क्रय शक्ति के आधार पर डालर की बाजार कीमत से लगभग 4 गुना ज्यादा मूल्यवान है। यानि हमारी प्रतिस्पर्द्धी लागत दुनिया से और अधिक कम हो सकती है। इसलिए भारत से निर्यात बढ़ने की खासी अच्छी संभावनाएं है लेकिन उसके लिए सरकार को सतत् प्रयास करने होंगे। ❑❑

उत्तराखंड स्थित सिल्कियारा की सुरंग के सबक

सिल्कयारा सुरंग धसाव की घटना के बाद पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील हिमालयी इलाकों में सुरंग के निर्माण में नियमों की अनदेखी का मामला एक बार फिर उजागर हुआ है। नवयुग कंपनी द्वारा 865 करोड़ रूपये की लागत से बनायी जा रही साढ़े चार किलोमीटर लंबी सुरंग के धसने के बाद राज्य में बन रही सभी सुरंगों की समीक्षा की मांग उठ रही है।

मालूम हो कि दीपावली के दिन से ही उत्तराखंड की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी तथा उनके परिवार जनों के मन में अंधेरा छाया था। दुरुह पहाड़ का सीना काटने में विज्ञान और तकनीक से लैस मशीन ठिठकी,पर मनुष्य का हौसला जिंदगी की जंग जीतने में कामयाब हुआ। बाबा बौखनाग की असीम अनुकंपा से उत्तरकाशी के सिल्कवारा में बन रही सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। चट्टान का सीना चीरकर सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लेना खुशी की बात है। सभी देशवासियों के लिए भावुक कर देने वाला पल है, लेकिन घटनाक्रम को लेकर कई एक प्रश्न भी खड़े हुए हैं। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने में 17 दिन लग गए। इससे यह जाहिर हुआ कि बचाव कार्य के लिए हमारे पास कोई पक्की योजना नहीं है। हमें विदेश से भी मदद लेनी पड़ी। साथ ही यह भी सामने आया कि सिल्कयारा के जिस क्षेत्र में बन रही सुरंग में मजदूर फंसेइस जगह के आसपास दो स्थानीय फाल्ट की उत्तर से दक्षिण तक कटान है। तो क्या इस सुरंग को बनाने से पहले इसका अध्ययन नहीं किया गया था? बचाव कार्य के सिलसिले में आए विदेशी विशेषज्ञों ने शेयर जोन की बात कही, शेयर जोन उसे कहते हैं जिसके आसपास से दो नदियां एक दूसरे को क्रॉस करती है। मजदूरों ने भी सुरंग के बार–बार खसकने की शिकायत की थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या हिमालय क्षेत्र में विकास का कोई अच्छा रोडमैप हमारे पास अभी नहीं है।

पहाड़ों पर आई आपदाओं की श्रृंखला में यह मौजूदा आपदा भी मानव निर्मित ही है। पर्वतीय संसाधनों का अत्यधिक दोहन, विकास के नाम पर अनियमित अनियंत्रित निर्माण, विभिन्न विभागों द्वारा समय–समय पर दी जा रही चेतावनियों की उपेक्षा, डरावना भ्रष्टाचार और दूसरों के जीवन की कीमत पर लाभ उठाने का क्रूर लालच ही इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है।

–अनिल तिवारी

गंगा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले आईआईटी कानपुर के पूर्व प्रोफेसर गुरदास अग्रवाल उर्फ स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद जीने कहा था कि "खोदते खोदते एक दिन खो देंगे पहाड़"। पहाड़ी क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं को लेकर कही गई उनकी बातें सुनने वालों के कानों में खतरे की घंटी की तरह अब भी गूंजती होगी। लेकिन विकास

के प्रेत ने ऐसे मायावी संसार की रचना करने को ठानी है, जहां न तो यह घंटी सुनाई पड़ती है और न हीं जो होता है वह दिखाई पड़ता है। दरअसल बांधों, सड़कों, बिजली घरों और कंक्रीट और संगमरमर से बनने वाली इमारतों की चकाचौंध में यह पता ही नहीं चलता कि हम प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं? हम सुविधा से कब विलासिता और विनाश के दौर में प्रवेश कर जाते हैं इसका भान नहीं होता। जब कभी केदारनाथ जैसा बड़ा जल प्रलय, जोशीमठ की तरह बड़े पैमाने पर भू–स्खलन की घटना होती है तो हतप्रभ होकर हाय तौबा करते हैं, लेकिन आगे के लिए कोई सबक नहीं लेते।

उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग के क्षतिग्रस्त होने और उसमे मजदूरों के फंस जाने की घटना के बाद उत्तराखंड में अंधाधुंध विकास परियोजनाओं पर सवाल खड़े हुए हैं। ठीक है कि पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए तयआधुनिक परियोजनाएं आवश्यक है लेकिन अगर यही विनाश का कारण बनने लगे तो पुनर्विचार की भी जरूरत है। इंसान बेहतर जीवन की अभिलाषा रखता है और बेहतर जीवन स्तर विकास के बिना संभव नहीं है लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में चल रहे नित नए निर्माण से उन इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं और अधिक बढ़ने की आशंका है। कुछ समय पहले जोशी मठ में कई मकान धंस गए थे, सैकड़ो मकान में दरार आ गई थी। तब वहां के लोगों नेजोशीमठ की पहाड़ी के नीचे सुरंग से होकर गुजरने वाली एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना को घटना के लिए जिम्मेदार माना था। भू–वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पहाड़ों के कई शहर भूकंप के अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र में बसे और बढ़े हैं। इसलिए ऐसी जगह पर होने वाली थोड़ी सी भी हलचल भारी तबाही मचा सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनियंत्रित विकास ने पहाड़ों के कई शहरों को पहले से ही खतरे में डाल रखा है।

हाल के वर्षों में पहाड़ के लोगों ने कई आपदाएं करीब से देखी है, लेकिन उन आपदाओं से सबक नहीं ले पाए और उनके मिजाज को समझे बिना विकास परियोजनाओं को हरी झंडी देते चले गए। यही कारण है कि हमें लगातार इस तरह के संकटों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जल विद्युत परियोजनाओं का प्रारंभ से ही विरोध होता रहा है। अधिकांश वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का मानना है कि पहाड़ों पर चलाई जा रही विद्युत परियोजनाएं भविष्य में बड़े संकट का कारण बन सकती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र की तरह धड़ल्ले से तोड़फोड़ नहीं की जा सकती। पहाड़ी क्षेत्र का पर्यावरण पढ़ने, समझने के बाद ही परियोजनाओं को हरी झंडी दी जानी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पर बनने वाले बांधों से ग्लेशियरों के भी कमजोर पड़ने की तस्दीक हुई है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि आज विज्ञान निरंतर प्रगति पर है, लेकिन वह प्रकृति के सामने आज भी बौना ही है। पलक झपकते हथेली में सरसों उगा लेने के जुनून में अति उत्साही वैज्ञानिक प्रकृति के साथ विज्ञान की प्रतियोगिता कराएंगे तो किसी न किसी रूप में वे तबाही को ही आमंत्रित करेंगे। विज्ञान और वैज्ञानिक सोच का प्रयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए न कि मानव के विनाश के लिए। पूरी दुनिया के लिए यह एक स्थापित सच है कि बड़े बांधों ने समय पाकर बड़ा तांडव मचाया है। लेकिन हमारे देश में एक पक्ष द्वारा लगातार यह तर्क दिया जाता रहा है की एक निश्चित अवधि तक प्रकृति की मार झेलने में बड़े बांध समर्थ होते हैं, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक डंके की चोट पर वह निश्चित समय सीमा नहीं बताता।

आज विकास के नाम पर जो हवा महल खड़ा किया जा रहा है वह किसी न किसी तरह से आम आदमी की कब्र खोदने का काम कर रहा है। और इससे भी ज्यादा दुखद है कि हम बड़े शर्मनाक तरीके से ऐसे विकास पर अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। क्या हम विकास का कोई ऐसा ढांचा नहीं खड़ा कर सकते जिससे वहां के निवासियों को स्थाई रूप से फायदा हो? विकास की योजनाओं को शुरू करते समय गरीबों के लिए अनेक फायदे गिनाए जाते हैं, लेकिन गरीबों के लिए फायदा दिवास्वप्न ही साबित होता है, जो गरीब विकास योजनाओं से जुड़ते भी हैं वह भी ता–उम्र गरीब ही बने रहते हैं। शासन सत्ता तथा पूंजीदार लोग अपनी हैसियत बढ़ाते हैं और आमजन ठगे से जहां हैं वहीं खड़े रह जाते हैं।

पहाड़ों पर आई आपदाओं की श्रृंखला में यह मौजूदा आपदा भी मानव निर्मित ही है। पर्वतीय संसाधनों का अत्यधिक दोहन, विकास के नाम पर अनियमित अनियंत्रित निर्माण, विभिन्न विभागों द्वारा समय–समय पर दी जा रही चेतावनियों की उपेक्षा, डरावना भ्रष्टाचार और दूसरों के जीवन की कीमत पर लाभ उठाने का क्रूर लालच ही इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। सूचनाएं बताती हैं कि केवल उत्तरकाशी ही नहीं बल्कि अन्य पर्वतीय नगर भी ऐसे ही आसन्न खतरे के कगार पर है। अब सवाल है कि अब तक डरावनी लापरवाही प्रदर्शित करती रही सरकारें ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाती हैं। उत्तरकाशी ने फिर एक बार सबक दिया है जिससे सीख जाना चाहिए और हर स्तर पर ऐसी आपदाओं से बचने के सचेत प्रयास भी किए जाने चाहिए। अब जबकि मजदूरों को बचा लिया गया है तो हमें ऐसी कार्ययोजना पर विचार करना चाहिए ताकि तीव्र भूकंप जोन वाले हिमालय क्षेत्र में इस तरह के हादसों का दोहराव ना हो। ❑❑

उच्च शिक्षा; नये आयात

अनेक उत्प्रेरक कारकों के कारण उच्च शिक्षा में भारतीय शिक्षा प्रणाली तेजी से विकसित हो रही है। छात्रों ने मौजूदा सार्वजनिक और नए निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के बीच शिक्षा क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, वैश्विक सहयोग की उपलब्धता, अनुसंधान पर अधिक ध्यान केंद्रित करने, विशेष रूप से गुणवत्ता अनुसंधान के लिए एनएएसी, एनआईआरएफ, एआईसीटीई जैसे निकायों द्वारा इन संस्थाओं के मूल्यांकन में वृद्धि की उम्मीद करना शुरू कर दिया है।

बेहतर शिक्षा और परिणामस्वरुप रोजगार के अवसर की तलाश में छात्रों की एक बड़ी संख्या उच्च शिक्षा के लिए विदेश में पलायन कर रही है। वर्ष 2019 में विदेश में जाकर पढ़ने वालों की संख्या 5.83 लाख थी, तो वर्ष 2022 में यह बढ़कर 7.5 लाख से अधिक हो गई है। विदेशी डिग्री महंगी होने के बावजूद भारतीयों में उसके प्रति आकर्षण कम नहीं हो रहा है। चीन के छात्रों में विदेशी शिक्षा को लेकर उदासीनता बढ़ने की खबरें हैं, जबकि भारतीय छात्रों में विदेशी शिक्षा के प्रति अभी भी ललक है।

इस पृष्ठभूमि में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थाओं का भारत में कैंपस खोलना हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए एक रोमांचक क्षण है। वे निश्चित रूप से यहां अध्ययन को नई प्रेरणा दे सकते हैं। भारतीय छात्रों को जेब खर्च किए बिना या स्थान परिवर्तन के बिना विदेश के कुछ सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में उपलब्ध शिक्षा प्राप्त हो सकती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की खोज में यह प्रयोग भौगोलिक रूप से अधिक सुलभ होने के कारण वित्तीय भार को कम करेगा, वहीं कर्मचारियों को अंतरराष्ट्रीय और दुनिया भर के छात्रों को एक साथ एक शैक्षिक केंद्र में रहकर विकसित होने का मौका देगा।

विदेशी शिक्षण संस्थानों के आने से भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक नए चरण की शुरुआत हो सकती है। समय के साथ प्रमुख संस्थाओं का लक्ष्य न केवल भारतीय छात्रों, जो वर्तमान में सभी विदेशी छात्रों के कब्जे वाली बेचों पर पीछे बैठते हैं, को समायोजित करने के लिए भारतीय परिसर स्थापित करना होगा, बल्कि आसपास के देशों के छात्रों को भी समायोजित करना होगा। भारतीय संकाय को इन संस्थाओं द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने का अवसर मिलने के मामले में भी लाभ होगा। इतना ही नहीं, जब तक यह संस्थान यहां रहेंगे वे अपने भारतीय समकक्षों और भारतीय उद्योग के साथ सहयोग करेंगे और भारतीय परिवेश के लिए प्रासंगिक अनुसंधान और नवाचार का उत्पादन करेंगे। इसका लाभ छात्रों, शिक्षा, जगत, उद्योग, अर्थव्यवस्था और समाज को होगा। संभावना व्यक्त की जा रही है कि भारत वैश्विक उच्च शिक्षा परिदृश्य में तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देगा।

फिर भी इस उत्साह को बहुत अधिक सावधानी से लेने की आवश्यकता है, ऐसे कई अनूदित प्रश्न और बहस योग्य मुद्दे मौजूद हैं। उदाहरण के लिए नियम कहते हैं कि एक विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान को वैश्विक रैंकिंग में या विषय वार रैंक में 500 सर्वश्रेष्ठ में से एक होना होगा। लेकिन एक भी रैंकिंग एजेंसी नहीं है, ऐसी स्थिति में इस स्पष्ट के कारण यह बहुत संभव है की सर्वोत्तम विश्वविद्यालय से भी कम लोग पैसा कमाने की एकमात्र उद्देश्य से प्रवेश प्राप्त कर सकें।

ऐसी संभावना है कि भारत में उच्च शिक्षा की औसत फीस बढ़ सकती है। यदि विदेशी संस्थान अपने प्रिंसिपलों को पैसा वापस भेज सकते हैं तो उनके मुनाफाखोरी में संलग्न होने

देश को विश्व स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा में काफी इनपुट और निवेश की आवश्यकता है। इसी प्रकार विदेशी मदद से अनुसंधान उत्पादन को निश्चित रूप से काफी बढ़ावा मिलेगा।

– डॉ. जया कक्कड़

की भी आशंका है। इतना ही नहीं इससे सीधे तौर पर उनसे प्रतिस्पर्धा करने वाले घरेलू संस्थान आईआईटी आईआईएम भी अपनी फीस बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। अगर इन विदेशी विश्वविद्यालयों को पैसा कमाने की इजाजत नहीं है तो उन्हें भारत में कैंपस स्थापित करने में दिलचस्पी क्यों है?

सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि केवल गंभीर खिलाड़ी ही इस रास्ते से भारत में प्रवेश करें। इस प्रकार यह अनिवार्य कर दिया गया है कि फ्रेंचाइजी अध्ययन या शिक्षक केंद्रों को अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह मुख्य परिसर में छात्रों के नामांकन के लिए विपणन के एकमात्र उद्देश्य से संचालित होते हैं। लेकिन फिर अगर यह गंभीर खिलाड़ी घरेलू स्तर पर उपलब्ध प्रतिस्पर्धी और सक्षम संकाय सदस्यों पर कब्जा कर लेते हैं तो इन विदेशी संस्थाओं को दी गई पूर्ण स्वायत्तता अतिरिक्त बौद्धिक लाभ के मामले में बहुत कम लाभ के समान होगी। लेकिन दूसरी ओर स्थानीय प्रतिभा को विदेशी संकाय सदस्यों से अप्रत्यक्ष प्रवेश स्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और वह बेहतर प्रशिक्षण की इच्छा रखेंगे। 'नया सामान्य' क्या होगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है।

यूजीसी अकेले परिसर स्थापित करने के लिए आवेदनों की जांच करेगा। एफएचईआई की अपनी प्रवेश नीतियां, शुल्क संरचनाएं, पाठ्यक्रम होंगे, वह अपनी डिग्री प्रदान करेंगे और अनुसंधान करेंगे। यूजीसी के पास पाठ्यक्रमों शिक्षा की गुणवत्ता उसकी उपयोगिता, प्रदान की गई डिग्री की संख्या और स्नातक करने वाले छात्रों की निगरानी करने की शक्ति होगी। सामान्य तौर पर सर्वश्रेष्ठ विदेशी संस्थान विदेशी परिसर स्थापित करने में झिझक महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें अपने लोकाचार और परंपराओं को आयात करना मुश्किल लगता है। इसके अलावा यूजीसी की जांच उनके लिए स्वागत योग्य नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर यूजीसी को लगता है कि यह पाठ्यक्रम से भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचता है तो यूजीसी के पास अनुमति को निलंबित करने या वापस लेने की शक्ति होगी। लेकिन यह एक बहुत ही व्यक्तिपरक मूल्यांकन है। इसी तरह यह भी स्पष्ट नहीं है कि यूजीसी पढ़ाए गए पाठ्यक्रम की गुणवत्ता का पता कैसे लगाएगी, मूल्यांकन करने के लिए मानदंड क्या होंगे और इस गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए किसे नियुक्त किया जाएगा?

शायद एक सहयोगी मॉडल से भारत और विदेशी साझेदारों दोनों को लाभ हो सकता है। इन विदेशी संस्थाओं को भारत में परिसरों की स्थापना और संचालन के लिए विनियमन के तहत आमंत्रित किया जा रहा है यह विनियमन इस बात पर जोर देता है कि एफएचएए के पास अकादमिक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करने के लिए भौतिक, शैक्षणिक और अनुसंधान बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के साथ एक स्वतंत्र परिसर होना चाहिए। लेकिन एफएचएआई ऐसा क्यों करेगा? सिवाय उसके कि जब उसे निवेश पर रिटर्न का दोगुना का आश्वासन दिया गया हो। इसीलिए बेहतर होता कि सरकार एक सहयोगी कैंपस मॉडल की अनुमति देता जिससे दोनों भागीदारों को लाभ होता।

इन संस्थाओं को आमंत्रित करने के पीछे एक उद्देश्य भारत को एक आकर्षक वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाना है। ऐसा क्यों होगा। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में केवल 333 एफएचईआई है। खैर, यह कई संभव बातों पर निर्भर करता है पहले कौन से एफएचएआई हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं। दूसरा वह कौन से कार्यक्रम पेश करने का निर्णय लेते हैं? तीसरा, क्या वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय प्रतिभा को शामिल करेंगे, चौथा, छात्रों का चयन कैसे होगा, पांचवा, कौन से गुणवत्ता पैरामीटर तैनात किए जाएंगे? छठवां, गुणवत्ता कैसे कायम रहेगी। यह सूची काफी लंबी है।

इन सबके बीच इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश को विश्व स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा में काफी इनपुट और निवेश की आवश्यकता है। इसी प्रकार विदेशी मदद से अनुसंधान उत्पादन को निश्चित रूप से काफी बढ़ावा मिलेगा। यदि भारतीय छात्रों को कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है तो एफएचएआई को आमंत्रित करने के भी नियमन से मदद मिलेगी साथ ही अगर इसका मतलब इन संस्थाओं द्वारा छात्रों जो आईआईटी, आईआईएम आदि में जा सकते थे और संकाय जहां भी पढ़ सकते थे का अवैध शिकार होगा? तो यह बहस का मुद्दा है कि भारतीयों को कितना शुद्ध लाभ इस तरह की शिक्षा से होगा। हालांकि अभी शुरुआती दिन है समय के साथ परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ❑❑

कॉप-28: पर्यावरण और लोगों की जान बचाने के लिए छोड़ना होगा पेट्रोलियम उपयोग

अगर जल्दी हम पेट्रोलियम ईंधन के उपयोग को न्यूनतम नहीं करेंगे तो न तो हम अपना पर्यावरण बचा सकते हैं और न ही हर साल लाखों लोगों की जान। दुबई में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन, कॉप28 में साझा रूप से सभी देशों को पेट्रोलियम ईंधन के उपयोग में कटौती करने का आग्रह किया गया। इसी सम्मेलन में एक वैश्विक अध्ययन के हवाले से यह बताया गया कि 2019 में दुनिया भर में हुई 80 लाख से अधिक मौतों में से लगभग 60 प्रतिशत मौत का कारण पेट्रोलियम ईंधन से निकला प्रदूषण था। ऊर्जा जरूरतों का अभी भी 40 प्रतिशत से अधिक स्रोत पेट्रोलियम ईंधन से आता है।

भारत और चीन सबसे ज्यादा प्रभावित

एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है कि पेट्रोलियम ईंधन की जगह यदि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाए तो दुनिया भर में वायु प्रदूषण से होने वाली प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख अतिरिक्त मौतों को रोका जा सकता है। उल्लेखनीय है कि वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा मौतें चीन और भारत में होती हैं। वैज्ञानिकों ने दुबई में पेश किए गए अपने शोध में बताया कि चीन में वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की संख्या सबसे अधिक है। यहां प्रति वर्ष 24 लाख से अधिक मौतें वायु प्रदर्शन से होती हैं। भारत में भी इसके कारण 21 लाख से अधिक मौतें होती हैं।

भारत और चीन ही दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं और दोनों ही पेट्रोलियम ईंधन के सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं। चीन में 2022 में पेट्रोलियम तेल की खपत रोजाना 14.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन थी। 1998 से 2021 के बीच चीन में प्रति दिन 10 मिलियन बैरल से अधिक की खपत बढ़ती चली गई थी। भारत भी पहले से कहीं अधिक डीजल, पेट्रोल और पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का उपयोग कर रहा है। तेल मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2023 में समाप्त वित्तीय वर्ष में, भारत ने 222.30 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों की खपत की, जो पिछले वर्ष से 10.2 प्रतिशत अधिक है। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता हैं।

चीन में भले ही पिछले दशक में वायु प्रदूषण कुछ कम हुआ है, लेकिन वह अभी भी काफी हद तक पेट्रोलियम ईंधन पर निर्भर है। चीन की एक बड़ी जनसंख्या बूढ़ी हो रही है। इस कारण जोखिम भी बढ़ रही है। चीन में पुरानी बीमारियाँ तेजी से फ़ैल रही हैं, जो विशेष रूप से बुजुर्गों को प्रभावित करती हैं।

–विक्रम उपाध्याय

कॉप 28 दुबई बैठक में भविष्य की तैयारी

2050 तक संयुक्त राष्ट्र के जलवायु तटस्थता के लक्ष्य के अनुरूप स्वास्थ्य में सुधार और जीवन बचाने के लिए पेट्रोलियम ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के उपायों पर कॉप–28 एक प्रभावी चर्चा हुई। कॉप–28 में ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थानों के वैज्ञानिकों ने कहा कि यदि पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग की जगह नवीकरणीय ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों तक हम पहुंच जाये तो वायु प्रदूषण का पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर जोखिम कम हो सकता है। ऐसा करना बहुत मुश्किल नहीं है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, 2020 में दुनिया भर में 29 प्रतिशत बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न हुई और उम्मीद है कि 2023 और 2024 में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 55 प्रतिशत वृद्धि चीन से ही होगी।

लगातार गर्मी में इजाफा

इस वर्ष भी रिकॉर्ड गर्मी रही है। सूखा, लू, बाढ़ और मूसलाधार बारिश के कारण दुनिया भर में हजारों लोगों की जान गई है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के पेरिस समझौते पर प्रगति का जायजा लिया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरिस समझौते का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व–औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है और इसके लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना जरूरी है।

इस मामले में चीन और अमेरिका के बीच मीथेन और गैर–कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) ग्रीनहाउस गैसों पर संयुक्त शिखर सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये दोनों देश कार्बन उत्सर्जक देशों में शीर्ष पर हैं। पहली बार बीजिंग और वाशिंगटन 2035 तक उत्सर्जन–कटौती योजनाओं में मीथेन को शामिल करने पर सहमत हुए हैं। पहली बार चीन ने भी यह प्रतिज्ञा की है कि वह गैर–CO_2 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के साथ–साथ वन हानि और प्लास्टिक पर अंकुश लगाने के लिए मिलकर काम करेगा।

चीन खुद बहुत परेशान

चीन में भले ही पिछले दशक में वायु प्रदूषण कुछ कम हुआ है, लेकिन वह अभी भी काफी हद तक पेट्रोलियम ईंधन पर निर्भर है। चीन की एक बड़ी जनसंख्या बूढ़ी हो रही है। इस कारण जोखिम भी बढ़ रहा है। चीन में पुरानी बीमारियाँ तेजी से फ़ैल रही हैं, जो विशेष रूप से बुजुर्गों को प्रभावित करती हैं। सूक्ष्म कण (ज्यादातर पीएम2.5) और ऑक्सीडेंट (ज्यादातर ओजोन) फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर रहे हैं, जिससे श्वसन और हृदय रोग के साथ–साथ कैंसर की बीमारियां भी हो रही हैं। वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से पुरानी बीमारियाँ बिगड़ जाती हैं जो मृत्यु दर बढ़ने का कारण बनती हैं।❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

बर्बादी का दूसरा नाम है मुफ्तखोरी

हाल ही में देश के पांच महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव संपन्न हुए। चुनाव हमारे लोकतंत्र के उत्सव के रूप में जाने जाते हैं। आजादी के बाद चुनावों की सतत प्रक्रिया के चलते, भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रीय देश के रूप में उभरा है। यह समय है, राजनीतिक दलों द्वारा अपने–अपने चुनाव घोषणा–पत्रों के माध्यम से मतदाताओं को अपने दलों की नीतियों और प्रस्तावित कार्यक्रमों से अवगत करवाने का।

इतिहास में सभी राजनीतिक दल, मतदाताओं को अपने वादों से लुभाने का प्रयत्न करते ही रहे हैं, लेकिन पिछले लगभग ढेड़ दशक में चुनावी वादों का प्रकार बदला है। इन वादों में नीतिओं और कार्यक्रमों की बजाए नकद राशि हस्तांतरण और मुफ्त की स्कीमों की घोषणायें प्रभुखता से होने लगी हैं। महिलाओं, किसानों, विद्यार्थियों और कई बार अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर वर्गों को नकद हस्तांतरण, समस्त जनता को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त यात्रा समेत कई मुफ्तखोरी की स्कीमों की घोषणायें, अब एक आम बात हो गई है।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के कर्ज माफ करने के अलावा, मुफ्त बिजली, गैस सिलेंडर की सब्सिडी, महिलाओं को 1500 रूपये प्रति माह, युवाओं को 3000 रूपये बेरोजगारी भत्ते के अलावा, कई अन्य मुफ्त की स्कीमों की घोषणा की गई। इसी प्रकार की घोषणायें अलग–अलग राजनीतिक दलों द्वारा की गई। मतदाताओं को रिझाने का हर संभव प्रयास किया गया।

जब कोई प्रांत मुफ्त की योजनाओं पर अपने कर राजस्व का इतना बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है तो स्वाभाविक रूप से आवश्यक सेवाओं और बुनियाद ढ़ांचा पर उसका पूँजीगत खर्च कम हो जाता है। राज्य सरकार पर कर्ज बढ़ता चला जाता है, जिसके चलते भविष्य में भी सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ–साथ यातायात और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित होती हैं।
– स्वदेशी संवाद

ऐसे में विचार करने का विषय है कि क्या यह हमारे लोकलंत्र की स्वस्थ परंपरा है। क्या हमारी सरकारें इन मुफ्त स्कीमों के लिए धन जुटा पायेंगी? कहीं राज्य सरकारों पर कर्ज का बोझ तो नहीं बढ़ जायेगा? इन मुफ्त की योजनाओं का सरकारी योजनाओं, सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च और उनके स्तर पर इनका क्या प्रभाव पडेगा? इन सभी प्रश्नों पर विचार करना जरूरी हो गया है।

अन्य देशों के उदाहरण

दुनिया के कई देशों में मुफ्तखोरी के कारण सरकारी कर्ज के बढ़ने और कई देशों के तो उसके कारण बर्बाद होने के भी कई उदाहरण मिलते हैं। वेनेजुएला और श्रीलंका इत्यादि के उदाहरणों से पता चलता है कि उन जैसे धनाढ़य देश भी मुफ्तखोरी की गलत आर्थिक नीतियों के चलते गरीब देशों से भी बदतर हालत में पहुंच सकते हैं, तो पाकिस्तान सरीखे विकासशील देशों की बिसात ही क्या है। वर्तमान में कल्याणकारी राज्य के नाम पर मुफ्त की स्कीमों के कारण कई अमीर देशों की भी एक लंबी सूची है, जो आज भारी कर्ज में डूबे हुए हैं और अब वे इन स्कीमों को चलाने में सक्षम नहीं हैं।

राज्यों पर बढ़ता कर्ज़

लेकिन मुफ्तखोरी की यह बीमारी अब भारत के कई राज्यों में फैलती जा रही हैं। इस माह होने वाले चुनावों में तो राजनीतिक दलों ने मुफ्तखोरी की योजनाओं की

झड़ी लगा दी है। मुफ्त बिजली, मुफ्त यातायात, महिलाओं को अनुदान राशि, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, इत्यादि के साथ–साथ मुफ्त वाहन और कई अन्य मुफ्तखोरी की स्कीमों के बारे में हम रोज सुन रहे हैं। कुछ समय पहले भारतीय रिजर्व बैंक और भारत के महालेखाकार एवं अंकेक्षक (कैग) ने अपनी–अपनी रिपोर्टों में मुफ्तखोरी के कारण राज्यों पर बढ़ते कर्ज के बारे में आंकड़े प्रकाशित किए हैं और यह चिंता व्यक्त की है कि जहां–जहां मुफ्तखोरी की स्कीमें ज्यादा चल रही हैं, वहीं–वहीं पर राज्यों पर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है।

गौरतलब है कि एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार किसी भी राज्य में ऋण–जीएसडीपी (राज्य का सकल घरेलू उत्पाद) का लक्षित अनुपात 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन 'कैग' का कहना है कि देश के अधिकांश राज्यों में यह अनुपात इस लक्षित अनुपात से कहीं ज्यादा है। पंजाब में यह 48.98 प्रतिशत, राजस्थान में 42. 37 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 37.39 प्रतिशत, बिहार में 36.73 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 35.30 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 31.53 प्रतिशत, तेलंगाना में 27.80 प्रतिशत, तमिलनाडु में 27.27 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 26.47 प्रतिशत तक पहुंच गया है। और यदि राज्य के सरकारी उद्यमों और राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को भी शामिल कर लिया जाए तो 2020–21 तक राजस्थान में ऋण जीएसडीपी अनुपात 54.94 प्रतिशत और पंजाब में तो यह 58.21 प्रतिशत तक पहुंच चुका था। आंध्र प्रदेश में भी यह 53.77 प्रतिशत आकलित किया गया है। इसके बाद तेलंगाना में यह 47.89 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 47.13 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल और बिहार में भी यह क्रमशः 40. 35 प्रतिशत और 40.51 प्रतिशत है, और तमिलनाडु में यह 39.94 प्रतिशत। कैग का यह भी कहना है कि राज्यों का कर्ज लक्षित अनुपात की तुलना में लगातार बढ़ता जा रहा है। यह राज्यों के लिए ही नहीं, देश के लिए भी चिंता का विषय है।

आंध्र प्रदेश के बारे में रिजर्व बैंक का कहना है कि पंजाब के बाद आंध्र प्रदेश मुफ्त की योजनाओं पर खर्च करने वाला देश का दूसरा ऐसा राज्य है। गौरतलब है कि पंजाब में कुल कर राजस्व का 45.5 प्रतिशत मुफ्त की योजनाओं पर खर्च होता है और आंध्र प्रदेश में 30.3 प्रतिशत। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो पंजाब में राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.7 प्रतिशत मुफ्त की योजनाओं में खर्च होता है तो आंध्र प्रदेश में 2.1 प्रतिशत। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सब्सिडी पर खर्च कर राजस्व का 28.8 प्रतिशत, झारखंड में यह 26.7 प्रतिशत है।

गौरतलब है कि 'कैग' के आकलन के अनुसार उन राज्यों पर कर्ज ज्यादा है, जहां मुफ्त की स्कीमों पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है। इसमें सबसे ऊपर पंजाब और आंध्र प्रदेश है। जहां कुल राजस्व का भारी हिस्सा मुफ्त की योजनाओं पर खर्च होता है। आंध्र प्रदेश के अलावा दक्षिण का एक अन्य प्रांत तमिलनाडु है, जो जरूरत से ज्यादा मुफ्त की योजनाओं पर खर्च करता है।

ज़रूरी मदों पर ख़र्च में कटौती

जब कोई प्रांत मुफ्त की स्कीमों पर अपने कर राजस्व का इतना बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है तो स्वाभाविक रूप से आवश्यक सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका पूँजीगत खर्च कम हो जाता है। राज्य सरकार पर कर्ज बढ़ता चला जाता है, जिसके चलते भविष्य में भी सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ–साथ यातायात और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। किसी भी राज्य के विकास के लिए जरूरी है कि उसमें निवेश बढ़े। इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में निवेश प्रभावित होता है और उसके कारण राज्य का विकास भी। जरूरी है कि राज्यों द्वारा दी जा रही मुफ्त की स्कीमों पर अंकुश लगाकर देश के विकास को गति दी जाए।

रेटिंग पर भी असर

हमें समझना होगा कि भारत राज्यों का एक संघ है, इसलिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ऋण मिलाकर संपूर्ण सरकार के ऋण माने जाते हैं। जहां एक तरफ केन्द्र सरकार कोरोना काल में अपने ऋण जो सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के 61 प्रतिशत तक पहुंच गया था, को 56 प्रतिशत तक घटाने में सफल हो चुकी है, लेकिन विभिन्न राज्य सरकारों के ऋण राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में संपूर्ण सरकार पर कर्ज बढ़ने के कारण देश की आर्थिक रेटिंग घटती जा रही है। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो हमारे देश को निवेश मिलने में तो कठिनाई होगी ही, हमारी कंपनियों और सरकार के द्वारा जो विदेशों से ऋण लिया जाता है उस पर भी ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। यानि बढ़ते कर्ज न राजकोषीय असंतुलन पैदा कर रहे हैं, बल्कि राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाएं चलाने की क्षमता को भी प्रभावित कर रहे हैं और देश और उद्योग के विकास के लिए भी मार्ग अवरूद्ध कर रहे हैं। राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते देश को मुश्किल में न डाल सकें, इसके लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। राजनीतिक कारणों से विधायिका और सरकारी तंत्र शायद इस काम में सफल न हो सके, लेकिन हमारे लोकतंत्र के अन्य स्तंभों जैसे न्यायपालिका और मीडिया को इस हेतु आगे आना होगा। ❑❑

आतंक के रक्तबीज हमास के इज़राएल पर आक्रमण की पृष्ठभूमि

(गतांक से आगे .....)

स्वदेशी पत्रिका के नवंबर अंक में हमास द्वारा इजराएल पर 7 अक्तूबर 2023 के आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि पर चर्चा की गयी थी। इस अंक में आगे की परिस्थितियों और अल्प युद्ध विराम के बाद फिर से हमास द्वारा फिर से इजराएल पर हमलों की वर्तमान विभीषिका पर चर्चा की गयी है।

53 दिन पुराने इज़राइल–हमास युद्ध की भयावहता 7 अक्टूबर 2023 को अपहृत बंधकों की रिहाई के लिए 7 दिनों के नाजुक संघर्ष विराम के बाद भी जारी है। यह हमास के उसी आतंकवादी आक्रमण की परिणिति है जब हमास के आतंकवादियों ने गाजा की सैन्यीकृत सीमा को तोड़ते हुए दक्षिणी इज़राइल में प्रवेश किया। इजरायली आधिकारिक सूचना के अनुसार लगभग 1,200 लोगों की हत्या कर गयी, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे, और लगभग 240 का अपहरण कर लिया था। इज़राइल ने गाजा में एक निरंतर सैन्य अभियान के साथ जवाबी हमला किया, जिसमें हमास शासित क्षेत्र के अधिकारियों का कहना है कि लगभग 15,000 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर नागरिक भी शामिल थे।

इजरायल के राष्ट्रपति श्री इसहाक हर्ज़ोग ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से निवेदन किया था कि वह अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके गाजा में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी इजरायली बंधकों को मुक्त कराने में सहायता करें।

यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर और मिस्र बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता कर रहे थे, जिसके कारण अब तक 99 इजरायलियों और विदेशियों को रिहा किया जा चुका है। संघर्ष विराम के परिणामस्वरूप 240 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 80 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया था। अन्य 25 बंधकों, जिनमें अधिकतर थाई लोग थे, को युद्धविराम समझौते के दायरे से बाहर मुक्त कर दिया गया। अन्य 25 बंधकों, जिनमें

(गाजा पट्टी में एक अज्ञात स्थान पर हमास के बंदूकधारियों के साथ बंधकों का चित्र)

आतंकवाद विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है लेकिन हमास, हिजबुल्लाह, आईएसआईएस, बोको हराम, तालिबान, लश्कर ए तैयबा आदि जैसे आतंकवादी संगठन शत्रु देशों में नृशंस हमले, क्रूर अत्याचार और मौत का तांडव फैलाने के लिए किसी भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

– विनोद जौहरी

अधिकतर थाई लोग थे, को युद्धविराम समझौते के अनुसार मुक्त कर दिया गया।

इज़राइल के प्रधानमंत्री के कार्यालय ने शुक्रवार (1 दिसंबर 2023) को हमास पर इज़राइली क्षेत्र में गोलीबारी करके संघर्ष विराम की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि वह अभी भी युद्ध के हमास को समाप्त करने के अपने लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध है। वक्तव्य में आरोप लगाया गया कि हमास ने सभी महिला बंधकों को मुक्त करने के अपने दायित्व को पूरा नहीं किया और इजरायली नागरिकों पर रॉकेट दागे।

इज़राइल की सेना ने 1 दिसंबर 2023 को कहा कि उसने हमास पर शर्तों का उल्लंघन करने और इज़राइली क्षेत्र की ओर गोलीबारी करने के कारण फिर से युद्ध प्रारम्भ कर दिया है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार प्रातः (30 नवंबर 2023) भीड़ भाड़ के समय के दौरान हमास द्वारा यरूशलेम में एक बस स्टॉप पर गोलीबारी में तीन लोग मारे गए।

इज़राइल सरकार ने युद्ध के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। बंधकों को मुक्त करना, हमास को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना कि गाजा फिर से इज़राइल के निवासियों के लिए खतरा न बने, यही हमास के विरुद्ध युद्ध के लक्ष्य हैं। इजरायल सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा था कि गाजा पट्टी में संघर्ष विराम समाप्त होने और शत्रुता फिर से प्रारम्भ होने के बाद हमास सबसे भयंकर हमले करेगा। सरकार के प्रवक्ता इलोन लेवी ने एक विनिर्देशन में कहा, "दुर्भाग्य से हमास ने सभी अपहृत महिलाओं को रिहा करने में विफल होकर विराम समाप्त करने का फैसला किया।" "हमारी महिलाओं को अपहरण में रखने के निर्णय के बाद, हमास अब सबसे भयंकर प्रताड़नाओं को अंजाम देगा।" लेवी ने

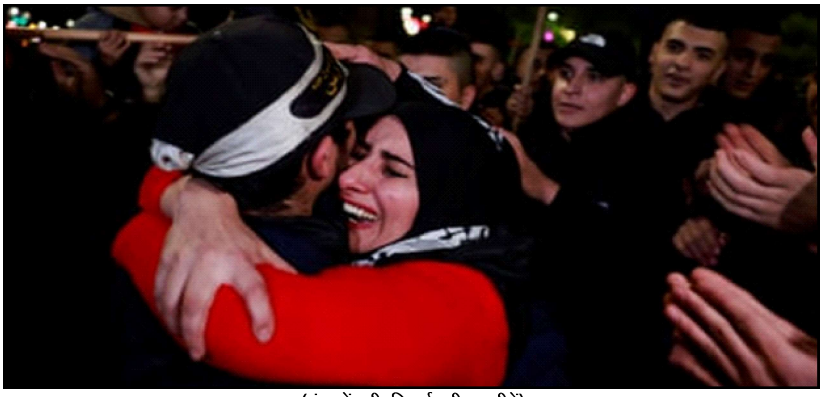

(बंधकों की रिहाई की तस्वीरें)

कहा कि सप्ताह भर चलने वाले समझौते को बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि इजरायली सरकार ने रिहाई के लिए फिलिस्तीनी कैदियों की एक सूची को पहले ही स्वीकृति दे दी थी तथा कैदी और बंधकों का आदान–प्रदान अगले दो दिनों तक और जारी रहता।

हमास ने कहा कि संघर्ष विराम विस्तार पर सहमत होने में विफलता का दोष इज़राइल पर है जिसने बंधकों की रिहाई के प्रस्तावों को लगातार अस्वीकार कर दिया था। इजराएली प्रवक्ता लेवी ने कहा कि हमास ने अभी भी 137 लोगों को बंधक बना रखा है, जिनमें से 10 की उम्र 75 या उससे अधिक है। उस संख्या में 117 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल थीं, जिनमें 126 इजरायली और 11 विदेशी नागरिक, आठ थाई, एक नेपाली नागरिक, एक तंजानिया और एक फ्रांसीसी–मैक्सिकन शामिल हैं ।

इज़राइल जेल विभाग ने शुक्रवार (1 दिसंबर 2023) को कहा कि उसने हमास के साथ संघर्ष विराम समझौते के तहत बंधकों के लिए नवीनतम विनिमय के रूप में इजरायली जेलों से 30 फिलिस्तीनियों को मुक्त कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इज़राइल जेल सेवा ने कहा कि सातवें अदला–बदली के तहत फिलिस्तीनियों को इजरायल, वेस्ट बैंक (इजरेली अधिकृत क्षेत्र) और यरूशलेम की जेलों से मुक्त कर दिया गया।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार (30 नवंबर 2023) को तेल अवीव में कहाः "स्पष्ट रूप से, हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं।" ब्लिंकन ने इजराइल से अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने और गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध में नागरिकों को रक्षित करने की मांग भी तेज कर दी। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि इज़राइल को "मानवीय नागरिक सुरक्षा योजनाएँ बनानी चाहिए जो निर्दोष फ़िलिस्तीनियों के हताहत होने को कम करें, जिसमें दक्षिणी और मध्य गाजा में क्षेत्रों नागरिकों के सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करें। युद्ध को स्थायी रूप से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र के सीओपी 28 के आयोजन के अवसर पर, फ्रांस ने इज़राइल और हमास के बीच संघर्ष विराम की समाप्ति पर खेद व्यक्त किया। जर्मनी के विदेश मंत्रालय का कहना है कि गाजा में संघर्ष विराम बहाल करने के लिए राजनयिक प्रयासों को दोगुना किया जाना चाहिए।

इज़राइल – हमास युद्ध की पृष्ठभूमि

1949 के बाद के वर्षों में, इज़राइल और मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के बीच तनाव बढ़ गया। 1956 के स्वेज संकट और सिनाई प्रायद्वीप पर इजरायल के आक्रमण के बाद, मिस्र, जॉर्डन और सीरिया ने इजरायली सैनिकों की

संभावित लामबंदी की प्रत्याशा में आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। जून 1967 में, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल गमाल नासिर के युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला के बाद, इज़राइल ने छह दिवसीय युद्ध शुरू करते हुए, मिस्र और सीरियाई वायु सेना पर पूर्व अनुमानित खतरों को भाँप कर हमला किया।

युद्ध के बाद इज़राइल ने मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी पर, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलम और सीरिया से गोलान हाइट्स अधिकृत कर लिए। छह साल बाद, जिसे योम किप्पुर युद्ध या अक्टूबर युद्ध कहा जाता है, मिस्र और सीरिया ने अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस पाने के लिए इज़राइल पर दो–मोर्चे से आश्चर्यजनक हमला किया; संघर्ष से मिस्र, इज़राइल या सीरिया को कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं हुआ, लेकिन मिस्र के राष्ट्रपति अनवर अल–सादत ने युद्ध को मिस्र की जीत घोषित कर दिया क्योंकि इससे मिस्र और सीरिया को पहले से सौंपे गए क्षेत्र पर बातचीत करने का अवसर मिल गया।

अंततः, 1979 में, संघर्ष विराम और शांति वार्ता की एक श्रृंखला के बाद, मिस्र और इज़राइल के प्रतिनिधियों ने कैंप डेविड शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे मिस्र और इज़राइल के बीच तीस साल के संघर्ष को समाप्त कर दिया। भले ही कैंप डेविड समझौते से इज़राइल और उसके पड़ोसियों के बीच संबंधों में सुधार हुआ, परंतु फ़िलिस्तीनी आत्मनिर्णय और स्वशासन का विवाद बना रहा। 1987 में, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में रहने वाले हजारों फिलिस्तीनियों ने इजरायली सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे पहले इंतिफादा के रूप में जाना जाता है।

1993 में, ओस्लो–I समझौते ने संघर्ष में मध्यस्थता की। फिलिस्तीनियों के लिए वेस्ट बैंक और गाजा में स्वशासन करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित की, और नव स्थापित फिलिस्तीनी प्राधिकरण और इज़राइल की सरकार के बीच पारस्परिक मान्यता स्थापित की। 1995 में, ओस्लो–II समझौते ने पहले समझौते का विस्तार किया, जिसमें प्रावधान किया गया जिनके अनुसार वेस्ट बैंक के 6 शहरों और 450 कस्बों से इज़राइल की पूर्ण वापसी अनिवार्य थी।

वर्ष 2000 में, वेस्ट बैंक पर इज़राइल के नियंत्रण पर विरोध के फलस्वरूप सितंबर 2000 में पूर्व इज़राइली प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल अल–अक्सा मस्जिद का दौरा किया जिस के बाद फिलिस्तीनियों ने दूसरा इंतिफादा शुरू किया, जो 2005 तक जारी रहा। जवाब में, इजरायली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के विरोध के बावजूद, 2002 में वेस्ट बैंक के चारों ओर एक बाधा दीवार के निर्माण को स्वीकृति दी।

फ़िलिस्तीनियों के बीच गुटबाजी भड़क उठी जब 2006 में हमास ने फ़िलिस्तीनी संसदीय चुनावों में जीत हासिल की और लंबे समय से बहुमत वाली पार्टी फ़तह को अपदस्थ कर दिया। इससे फिलिस्तीनी मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रेरित एक राजनीतिक और उग्रवादी आंदोलन हमास को गाजा पट्टी पर नियंत्रण मिल गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ हमास की चुनावी जीत को स्वीकार नहीं किया क्योंकि हमास को 1990 के दशक के अंत से पश्चिमी सरकारों द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है।

इज़राइल ने 2005 में गाज़ा और वेस्ट बैंक से अपने सैनिकों और निवासियों को वापस ले लिया, हालांकि उसने अपने हवाई क्षेत्र, साझा सीमा और समुद्री तटरेखा पर नियंत्रण जारी रखा। संयुक्त राष्ट्र अभी भी इस क्षेत्र को इजराइल के कब्जे वाला मानता है। हमास के नियंत्रण के बाद, हमास और फ़तह के बीच हिंसा भड़क उठी। वर्ष 2006 और 2011 के बीच, असफल शांति वार्ता और हिंसा का अंत एक समझौते के बाद हुआ। इसके अंतर्गत फतह और हमास ने वर्ष 2014 में साझा सरकार बनाई।

इज़राइल ने सदियों से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया है। यहूदियों को सदियों विनाश, अत्याचार, सामूहिक हत्याओं का सामना करना पड़ा है। हमास या हिजबुल्लाह या अरब देश कभी भी यहूदियों का विनाश नहीं कर पाएंगे। आतंकवादी संगठनों की आड़ में इजराइल के खिलाफ युद्धरत अरब देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय समझौतों की धज्जियां उड़ाई गयी हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ की संधियां और समझौते, युद्धविराम और शांति की पहल आतंकवादियों पर लागू नहीं होती हैं। आतंकवाद विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है लेकिन हमास, हिजबुल्लाह, आईएसआईएस, बोको हराम, तालिबान, लश्कर ए तैयबा आदि जैसे आतंकवादी संगठन शत्रु देशों में न्रशंस हमले, क्रूर अत्याचार और मौत का तांडव फैलाने के लिए किसी भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। यह इस्लामिक देशों का अपने आतंकवादी संगठनों की आड़ में शत्रु देशों के विरुद्ध छद्म युद्ध है जो उनकी सेनाएँ सामने से नहीं लड़ती परंतु इस्लामिक देश अपने आतंकवादी संगठनों को अपनी सभी सैन्य हथियार, मिसाइल, सैन्य नेटवर्क, संचार सुविधाएं, लॉजिस्टिक्स, लॉच पेड उपलब्ध कराते हैं। ऐसे भी समाचार मिलते हैं जब इन आतंकवादियों को घातक विदेशी हथियार, मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट आदि सप्लाइ होते है। यह किसी अंतर्राष्ट्रीय नियमों, समझौतों से बाध्य नहीं होते। इन युद्धों के परिणाम भयानक हैं और लाखों नागरिकों की हत्याएँ होती हैं और वैश्विक अशांति और युद्धोन्माद बना रहता है। ❑❑

तेज गति से बढ़ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार

भारतीय अर्थव्यवस्था आज लगभग 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विकास की राह पर आगे बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था के आकार में विस्तार से उस देश के नागरिकों की आय में वृद्धि दर्ज होती है इससे गरीब वर्ग के हाथों में भी पैसा पहुंचता है इससे, विभिन्न उत्पादों की मांग बढ़ती है एवं रोजगार के नए अवसर निर्मित होते हैं और अंततः गरीब वर्ग की संख्या में कमी होकर देश में मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ती है। नीति आयोग के एक प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2015–16 में भारत के शहरी क्षेत्रों में गरीब वर्ग की संख्या 24.85 प्रतिशत थी जो वर्ष 2020–21 में घटकर 14.90 प्रतिशत रह गई है। इसमें 9.95 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2015–16 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग़रीब वर्ग की संख्या 32.59 प्रतिशत थी जो वर्ष 2020–21 में घटकर 19.28 प्रतिशत रह गई है। अतः भारत में गरीब वर्ग की संख्या कम हुई है। इसी कारण से वैश्विक रेटिंग संस्थान भारत की रेटिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग संस्थान ने भारत की विकास दर को वर्ष 2023–24 के लिए 6 प्रतिशत रखा है तो वर्ष 2024–25 के लिए 6.9 प्रतिशत की बात की है। साथ ही इसी संस्थान का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2030 तक 7 लाख 30 हजार करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो जाने वाला है। वर्ष 2023 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 26 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के साथ प्रथम स्थान पर है। दूसरे नम्बर पर चीन आता है जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार 18 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है। तीसरे स्थान पर जापान है जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार 4 लाख 20 हजार करोड़ अमेरिकी डॉलर है। चौथे स्थान पर जर्मनी है जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार भी लगभग 4 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है। इस प्रकार भारत अपनी बढ़ी हुई लगभग 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की विकास दर के साथ शीघ्र ही जापान एवं जर्मनी को पछाड़ कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। फिच

विश्व के कई वित्तीय संस्थानों का मत है कि वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसका मतलब यह भी है कि देश में प्रति व्यक्ति आय में और अधिक तेज गति से वृद्धि की सम्भावना है। साथ ही, भारत आज प्रत्येक क्षेत्र में आत्म निर्भर भी बन रहा है।
– प्रहलाद सबनानी

नामक रेटिंग संस्थान ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के अपने पूर्व के अनुमान में सुधार करते हुए इसे वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 6.2 प्रतिशत कर दिया है, पहिले इस वृद्धि दर के 5.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। मूडीज नामक रेटिंग संस्थान ने भी भारत की विकास दर को वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 6.7 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की है। भारत तेजी से विकास कर रहा है यह त्यौहारों के दौरान बाजारों में उत्पादों की खरीद के लिए उमड़ रही भीड़ से भी साफ दिखाई दे रहा है।

भारत–24 चैनल पर प्रस्तुत एक कार्यक्रम में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, भारत का सकल घरेलू उत्पाद (अर्थात कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में कुल उत्पादन) वर्ष 2022–23 में 282. 83 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर आ गया है। अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद पूरे विश्व में पहिले नम्बर पर है जो 2121.19 लाख करोड़ रुपए का है। इसीलिए अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे अमीर एवं ताकतवर देश कहा जाता है। दूसरे नम्बर पर चीन का सकल घरेलू उत्पाद 1497.31 लाख करोड़ रुपए का है। जापान का सकल घरेलू उत्पाद 407.60 लाख करोड़ रुपए का है। जर्मनी का सकल घरेलू उत्पाद 341.05 लाख करोड़ रुपए का है। इस दृष्टि से भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अमीर देश है। वर्ष 2013–14 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 113.55 लाख करोड़ रुपए का था और वर्ष 2013–14 में भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरे विश्व में 10वां नम्बर था। वर्ष 2013–14 में अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद 1459.88 लाख करोड़ रुपए का था। चीन का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2013–14 में 871.77 करोड़ का था। जापान का सकल घरेलू उत्पाद 2013–14 में 349.37 लाख करोड़ रुपए का था। जर्मनी का सकल घरेलू उत्पाद 323.59 लाख करोड़ रुपए का था। अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद इस दौरान 50 प्रतिशत, चीन का 80 प्रतिशत, जापान का 30 प्रतिशत, जर्मनी का 5 प्रतिशत बढ़ा है जबकि भारत का सकल घरेलू उत्पाद 150 प्रतिशत बढ़ा है। इसी गति से भारत आर्थिक प्रगति करता रहा तो निश्चित ही वर्ष 2030 के पूर्व ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

आज भारत अपने घर में उत्पादित वस्तुओं के उपयोग को भी लगातार बढ़ा रहा है। "वोकल फोर लोकल" का नारा अब बुलंद हो रहा है एवं भारतीय नागरिक अब चीन में निर्मित उत्पादों का उपयोग कम करते हुए भारत में ही निर्मित वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं।

मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत भी बहुत काम होता दिखाई दे रहा है और भारत में निर्मित वस्तुओं का निर्यात लगतार बढ़ रहा है। वर्ष 2022–23 में भारत ने 36 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया है। जबकि वर्ष 2014 में 19.05 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। यह लगभग दोगुना हो गया है। वर्ष 2023–24 में भारत सरकार ने पूंजीगत व्यय को 10 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा दिया है। इससे रोज़गार के अधिक से अधिक अवसर निर्मित हो रहे हैं। वर्ष 2014–15 में भारत में 97,000 किलो मीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जो 9 वर्ष बाद वर्ष 2023–24 में बढ़कर 145,155 किलोमीटर हो गए हैं। इस दौरान लगभग 50,000 किलोमीटर के नए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित हुए हैं। अब तो गुणवत्ता के मामले में भारत के राजमार्ग अमेरिका के राजमार्गों से टक्कर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेहतरीन राजमार्ग विकसित देश के लिए जरूरी हैं। अच्छे राजमार्गों से बाजार और रोजगार दोनों बढ़ते हैं।

आज भारत अपने घर में उत्पादित वस्तुओं के उपयोग को भी लगातार बढ़ा रहा है। "वोकल फोर लोकल" का नारा अब बुलंद हो रहा है एवं भारतीय नागरिक अब चीन में निर्मित उत्पादों का उपयोग कम करते हुए भारत में ही निर्मित वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी भी भारतीय नागरिकों को लगातार अपील कर रहे हैं कि भारत में ही उत्पादित वस्तुओं का उपयोग

करें। इसका असर होता दिख भी रहा है। चीन से विभिन्न उत्पादों के आयात में इस त्यौहारी मौसम में कमी आई है और एक अनुमान के अनुसार इस वर्ष लगभग एक लाख करोड़ रुपए के उत्पादों का आयात चीन से कम हुआ है। चीनी दिवाली लाइट्स के आयात में 32 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। वहीं दूसरी ओर भारत में बनी लाइट्स की बिक्री में 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। इसका सबसे अधिक फायदा गरीब वर्ग को हो रहा है। हम समस्त भारतीय नागरिकों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सड़क के एक किनारे बैठकर कुछ वस्तुएं बेचने वाले गरीब व्यक्ति से अधिक मोलभाव ना करते हुए उनसे वस्तुएं खरीदें ताकि यह वर्ग भी अपनी आय को बढ़ा सके। वैसे भी, जब हम लोग माल से वस्तुएं खरीदते हैं तो कोई माल भाव थोड़ी करते हैं।

सकल घरेलू उत्पाद जब बढ़ता है तो लोगों की आय भी बढ़ती है। जब लोगों की आय बढ़ती है तो लोग बाजार में सामान खरीदते हैं। इससे बाजार में उत्पादों की मांग बढ़ती है। उत्पादों की मांग एवं आपूर्ति से उत्पादों की बाजार कीमतें तय होती है। जब किसी भी उत्पाद की मांग तुलनात्मक रूप से अधिक तेजी से बढ़ती है और उस उत्पाद की आपूर्ति बाजार में समय पर नहीं हो पाती है तो उस उत्पाद की बाजार में कीमतें बढ़ने लगती है। जब खर्च करने की क्षमता बढ़ती है तो आप सामान के दाम अधिक देने को भी तैयार रहते हैं। भारत में न केवल आर्थिक विकास में गति आ रही है बल्कि मुद्रा स्थिति भी नियंत्रण में है। यह केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से किए जा रहे उपायों के चलते सम्भव हो पा रहा है। भारत की वित्तीय नीतियां महंगाई को रोकने के साथ साथ विकास को भी बढ़ावा दे रही हैं। खाने पीने की वस्तुओं की बाजार कीमतों में कमी होने से अक्टोबर 2023 माह में खुदरा महंगाई की दर में गिरावट आई है और यह चार महीने के निचले स्तर 4.87 प्रतिशत पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति की दर सितंबर 2023 माह में पिछले तीन माह के निचले स्तर 5. 02 प्रतिशत पर थी।

भारत में आम आदमी का सबसे अधिक खर्च खाने पीने और स्वास्थ्य सेवाओं पर हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर 89 000 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया है। डॉक्टरों की संख्या में 4 लाख से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है। भारत में आज 13 लाख से अधिक एलोपेथिक डॉक्टर हैं। इसके अतिरिक्त, 5.65 लाख आयुर्वेदिक डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार भारत में प्रत्येक 834 नागरिकों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। गरीब नागरिकों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए आयुषमान स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार किसानों के लिए मोदी सरकार ने प्रति क्विंटल गेहूं पर 775 रुपए से, चावल पर 730 रुपए से न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। वर्ष 2012–13 में भारत के किसानों की औसत मासिक आय 6,426 रुपए पाई गई थी जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर 10,248 रुपए हो गई है। यूएनडीपी के एक प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि भारत में मिडल क्लास अर्थात मध्यम वर्ग की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वैश्विक स्तर पर मिडल क्लास की बढ़ रही संख्या में भारत का योगदान 24 प्रतिशत का है। विश्व के कई वित्तीय संस्थानों का मत है कि वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसका मतलब यह भी है कि देश में प्रति व्यक्ति आय में और अधिक तेज गति से वृद्धि की सम्भावना है। साथ ही, भारत आज प्रत्येक क्षेत्र में आत्म निर्भर भी बन रहा है। ❑❑

प्रहलाद सबनानीः सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर, म.प्र.

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

बेहतर प्रोत्साहन नीति में संकट का समाधान

धान की फसल के कटाई सीजन में एक बार फिर पराली जलाना खबरों में रहा। अब एक दशक से अधिक समय से, जब से पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली में आग लगाना ज्वलंत मुद्दा बन गया है, नई दिल्ली में कुख्यात वायु प्रदूषण के लिए किसानों को दोषी ठहराये जाने के साथ ही इस आग पर काबू पाने का संघर्ष अभी जारी है। हालांकि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने दावा किया कि पिछले तीन साल में खेतों में आग लगने की घटनाओं में कमी आई, लेकिन 1 नवंबर के बाद तीन दिनों में इसमें 150 प्रतिशत का उछाल नजर आया। जबकि कई एफआईआर दर्ज की गई व जुर्माना लगाया गया फिर भी खेतों में आग लगने का संकट जारी रहा। संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम को उन किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में 'रेड एंट्रीज' करने के लिए कहा गया जो धान के अवशेषों को न जलाने के निर्देश नहीं मान रहे थे।

लेकिन यहां एक पेच है जब पत्रकार कहते हैं कि उपलब्ध कराए गए उपग्रह डेटा के आधार पर आग लगने की घटनाओं की संख्या में कमी आई है, तो उन्हें यह अहसास नहीं होता कि वह क्षेत्र अधिक मायने रखता है जो आग से बचाया गया है। आग की संख्या में कमी समानुपातिक रूप से उस क्षेत्र में कमी से संबंधित नहीं है जिस पर पराली जलाई जाती है। उदाहरणतया, पंजाब ने दावा किया कि पिछले साल यानी 2022 के धान कटाई के मौसम में पिछले कुछ वर्षों में पराली जलाने की संख्या में 30 प्रतिशत की कमी आई, लेकिन जो क्षेत्र असल में खेत में पराली जलाने से बचाया गया था वह केवल 1.5 प्रतिशत था। यह दर्शाता है कि खेत में आग लगने की घटनाओं का डेटा कितना भ्रामक हो सकता है।

कटाई सीजन के शुरुआती कुछ हफ्तों में, आग लगने की घटनाओं में महत्वपूर्ण कमी को लेकर खबरें आयीं। एक बार फिर ये न्यूज रिपोर्ट्स ऐसा आभास देती रहीं कि अवशेष जलाने की समस्या का बहुत हद तक खयाल रखा गया। वहीं इन खबरों के प्रकाशित होने तक पूरी खड़ी फसल की कटाई भी नहीं हुई थी जबकि इस साल पंजाब में करीब 190 लाख टन धान की फसल होने का अनुमान था। इसके बाद, जब गेहूं बुआई के लिए खेतों

किसानों पर दबाव डालना, डंठल जलाने की समस्या का समाधान नहीं है। उनके साथ खड़े रहना, और पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना ही सही राह है। इस तरीके को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि फसल उठने के बाद के बजाय कटाई से पूर्व ही यह अनुदान की राशि वितरित कर दी जाये।

– देविंदर शर्मा

को तैयार करने का काम जोरों पर होगा तो आग लगाने की घटनाओं में तेजी जारी रहेगी।

इस वर्ष कटाई में देरी पंजाब में फसल रोपाई के सीजन के दौरान हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण हुई है (कुछ क्षेत्रों में, किसानों को सीजन में दो बार बाढ़ का सामना करना पड़ा) और पूरी फसल काटने में देर हुई है। इस बारे में हरियाणा बहुत बेहतर प्रदर्शन करता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जहां पंजाब में धान का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख हेक्टेयर है, वहीं हरियाणा में धान का रकबा लगभग 50 प्रतिशत कम है, उसमें भी एक अहम हिस्सा बासमती का है, जिसके डंठल अक्सर नहीं जलाए जाते हैं। दिलचस्प यह है कि एनसीआर सीमा से सटे जिलों में पराली जलाई नहीं जाती है। दरअसल, नई दिल्ली की वायु गुणवत्ता हरियाणा के पड़ोसी जिलों की वायु गुणवत्ता से कहीं अधिक खराब है। इससे पता चलता है कि नई दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों को राजधानी से आने वाले बढ़ते प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है।

हमें नहीं भूलना चाहिये कि पंजाब अकेला धान के औसतन करीब 220 लाख टन अवशेष उत्पन्न करता है। पराली की इतनी भारी मात्रा सरकार के साथ ही इंडस्ट्री मिलकर भी मैनेज नहीं कर सकती हैं। अब कुछ सालों से किसान कह रहे हैं कि वे बिना आग लगाये स्थानीय तरीकों से पराली का प्रबंधन कर सकते हैं बशर्ते ऐसा करने पर उन्हें प्रोत्साहन का भुगतान किया जाये। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपये की मांग की थी। मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी 1500 करोड़ रुपये की मांग की थी। केंद्र ने इन मांगों को मंजूर नहीं किया।

इसके बजाय केंद्र सरकार धान

हमें नहीं भूलना चाहिये कि पंजाब अकेला धान के औसतन करीब 220 लाख टन अवशेष उत्पन्न करता है। पराली की इतनी भारी मात्रा सरकार के साथ ही इंडस्ट्री मिलकर भी मैनेज नहीं कर सकती हैं। अब कुछ सालों से किसान कह रहे हैं कि वे बिना आग लगाये स्थानीय तरीकों से पराली का प्रबंधन कर सकते हैं, बशर्ते ऐसा करने पर उन्हें प्रोत्साहन का भुगतान किया जाये।

के डंठल के निपटारे की समस्या सुलझाने को और ज्यादा मशीनों पर जोर दे रही है। पहले ही पंजाब को सब्सिडी पर 1. 37 लाख मशीनें प्रदान की जा चुकी हैं, जिनमें इस साल दी गयी 20000 मशीनें भी शामिल हैं। जबकि ये मशीनें एक साल में ज्यादा से ज्यादा तीन सप्ताह ही प्रयोग की जाती हैं व बाकी समय अधिकतर बेकार पड़ी रहती हैं। यह भी कि पंजाब तेजी से मशीनों के कबाड़खाने में तब्दील हो रहा है जहां केवल एक लाख ट्रैक्टरों की जरूरत है लेकिन इसके मुकाबले यहां एक्सेसरीज समेत पांच लाख से ज्यादा ट्रैक्टर हैं। हालांकि, नीति निर्माताओं को आगामी वर्षों में राज्य के समक्ष आने वाली एक और समस्या के प्रति सचेत करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय लगता है हर कोई मशीनें बेचकर खुश हो रहा है।

डंठल जलाने की समस्या परिदृश्य में कंबाइन हारवेस्टर्स के आने के बाद पैदा हुई। इस समय पंजाब में करीब 15000 कंबाइन हारवेस्टर्स हैं जिनमें से केवल 6000 में ही स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) टेक्नोलॉजी लगी है। लेकिन किसान इस एसएमएस को पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें अतिरिक्त लागत आने के अलावा डीजल की भी अधिक खपत होती है। इसी प्रकार शुरुआत में प्रदान की गयी 13000 हैप्पी सीडर मशीनें बेकार पड़ी हैं क्योंकि अब किसान नयी पीढ़ी की सुपर सीडर मशीनें पसंद करते हैं। लेकिन पंजाब में खेतों में आग लगाने की घटनाओं में कमी का अच्छा चलन केवल बालर मशानों के आगमन के बाद आया। इस साल करीब 2300 बालर मशीनें आवंटित की गयीं।

इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट (स्क्रॉल. इन मार्च 21, 2019) में खेत की आग से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित लागत की तुलना की गई है, जिसे हर नीति निर्माता को जरूर पढ़ना चाहिए, और उम्मीद है कि रिपोर्ट एक ही बार में आंखें खोल देगी। इसमें कहा गया है कि फसल जलाने से हर वर्ष पर्यावरण और स्वास्थ्य व्यय के रूप में 2 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होता है। अगर इस नुकसान की वसूली की जाए तो यह 700 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) के लिए भुगतान करने को काफी होगा। यदि ऐसा है, तो मुझे पंजाब को प्रति वर्ष 2,000 करोड़ रुपये की ग्रांट देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं दिखता, अगर इससे किसानों को उस विशाल समस्या से निपटने में मदद मिल सकती है जिसका सामना समाज बड़े पैमाने पर कर रहा है। हम थोड़ी राशि बचाने के चक्कर में बड़ी रकम गवांने की मूर्खता नहीं कर सकते हैं।

नीति–निर्माताओं को जागना होगा। किसानों पर दबाव डालना, डंठल जलाने की समस्या का समाधान नहीं है। उनके साथ खड़े रहना, और पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना ही सही राह है। इस तरीके को और ज्यादा प्रभावी बनाने को जरूरी है कि फसल उठने के बाद के बजाय कटाई से पूर्व ही यह अनुदान की राशि वितरित कर दी जाये। ❑❑

https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/solution-to-the-crisis-in-better-incentive-policy/

विवेकानंद के विचार आज भी प्रासंगिक

स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण भारत के साथ साथ सम्पूर्ण मानव जाति के लिए वर्तमन में भी प्रासंगिक है तथा सदैव रहेगा भी। उनके इसी दृष्टिकोण पर विचार करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1984 को अन्तर्रराष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था तथा भारत सरकार ने तभी से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रुप में मनाने का संकल्प लिया था। विवेकानंद का दृष्टिकोण अथवा विचार था कि 'नरसेवा – नारायण सेवा'। यह विचार ही विश्व व्यापी बन गया तथा इस विचार को ही विश्व के युवा वर्ग ने भी स्वीकार किया। विवेकानंद का जीवन बहुत कम रहा उन्होनें मात्र 39 वर्ष पांच माह 12 दिन का जीवन जिया। भारत के साथ साथ सम्पूर्ण विश्व भी उनके विचारों से प्रेरणा ग्रहण कर रहा है। विवेकानंद ने भारतीय आत्मा को सार्वभौकिता के स्तर तक पंहुचाया। भारत की सनातनी संस्कृति को विश्व में स्वीकार करने के स्तर तक पंहुचाया। उनका पक्का विश्वास था कि भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, जो सम्पूर्ण संसार का पथ प्रदर्शन करने में समर्थ होगा। उनकी भविष्य वाणी सत्य होगी। इसमें विश्व की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए किसी प्रकार सन्देह नहीं रह जाता कि विश्व में 56 एक विचार के देश शान्ति से मीलें दूर है जो देश बचे है उनमें भी उन देशों की मानसिकता के कारण अशान्ति व अस्थिरता ही महसूस की जा रही है।

वर्तमान में भी भारत में विवेकानंद के विचारों की सर्वग्राह्यता है जिस कारण भारत अंखड़ बना हुआ है। उनके ही विचारों से प्रेरणा प्राप्त कर भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की उन्नति व विकास के लिए पांच सकंल्प लिये है। जिसकी घोषणा लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को की गई थी। देश के अमृत काल में विवेकानंद को इससे अच्छी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है कि उनके विचारों से बनाये पांच संकल्प राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकर किये जायें। पांच संकल्पों में – विकसित भारत, गुलामी से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों का कर्तव्य शामिल है।

स्वामी विवेकानंद भारतीय धर्म, अध्यात्म एवं दर्शन के सच्चे ध्वज वाहक थे। विवेकानंद का जीवन दर्शन संपूर्ण विश्व के लिए शांति, प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता तथा शक्ति से ओत प्रोत था। वे सदैव लक्ष्मीनारायण भगवान से पहले दरिद्र नारायण की सेवा के प्रबल पक्षधर थे।

– डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

विकसित भारतः एक नया भारत जो निकल पड़े मोची की दुाकन से, भड़भूजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झोपड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ो व पर्वतों और खेत खलिहानों से और पुनः भारत मां को विश्व गुरु के पद पर आसीन कर दे। विकसित भारत के महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबका साथ सबका विकास ही एक मात्र मंत्र है।

गुलामी से मुक्तिः भारत पहले मुसलमानों का तथा बाद में दो सौ वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। एक बार किसी ने 1897 में विवेकांनद से पूछा कि स्वामी जी मेरा धर्म क्या है? स्वामी जा ने कहा कि गुलाम का कोई धर्म नहीं होता है। आगामी 50 वर्षों तक सिर्फ भारत को गुलामी से आजाद कराना ही तुम्हारा धर्म है। अपने मनमस्तिष्क में गुलामी का कोई भी विचार न रहने दें। हमारें मन के किसी भी कोने में गुलामी का भाव नहीं रहना चाहिए क्योंकि हम वह है, जो हमें हमारी सोच ने बनया है।

विरासत का पर्वः स्वामी जी ने भारत के गुलामी के काल में 11 सितम्बर 1893 को अमेरिका के शहर शिकागो में भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, विरासत, अध्यात्म और वैभवशाली इतिहास के विषय में विश्व को बताया। भारत की विरासत के कारण ही भारत को स्वर्णकाल प्राप्त हुआ था और भारत सोने की चिड़िया कहलाया। हमें अपने देश की

समृद्ध विरासत पर गर्व करना चाहिए। भारत फिर से परम वैभव को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हुआ है। गुलामी के कारण भारतीयों में जो हीनता का भाव आया वह खत्म हुआ।

एकता व एकजुटताः स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि जल्दी ही प्रत्येक धर्म की पताका पर लिखा हो – विवाद नहीं, सहायता। विनाश नहीं, संवाद। मत विरोध नहीं, समन्वय और शांति। स्वामी जी ने कहा था कि इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो और अभिमान के साथ यह घोषणा करें कि हम भारतीय है और प्रत्येक भारतीय हमारा भाई है। नरेन्द्र मोदी ने भी आतंकववाद के विरुद्ध विश्व को यह संदेश दिया है। किसी देश की सबसे ताकत उस देश की एकता और एकजुटता में ही निहित होती है।

नागरिकों का कर्तव्यः स्वामी जी के अनुसार हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम अपने प्रति व अपने भाईयों के प्रति धृणा न करें। यह मूलभूत प्राण शक्ति है। नरेन्द्र मोदी ने कहा कि है कि नागरिकों का कर्तव्य ही देश और समाज की प्रगति का रास्ता तैयार करता है।

भारत ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की परन्तु गुलामी की मानसिकता से मुक्ति नहीं पायी। एक कहावत ही बन गई कि अंग्रेज चले गये और अग्रेजी व काले अग्रेजों को छोड़ गये। भारत में अभी भी एक परिवार विशेष के प्रति लोगों की गुलामी की मानसिकता दृष्टिगोचर होती है। देश में मात्र एक ही परिवार दिखाई देता है जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। नरेन्द्र मोदी स्वामी विवेकानंद के बताये मार्ग पर चलते हुए गुलामी की इसी मानसिकता को तोड़ने में जुटे हुए है। प्रत्येक भारतीय स्वंय को पहचानें, स्वंय का निर्माण करे, स्वंय का विकास करें, विश्व पटल पर स्वंय को प्रतिस्थापित करें तभी भारत आगे बढ़ पायेगा। भारत में स्वतंन्त्रता प्राप्ती

के अमृत काल में प्रधानमंत्री मोदी के द्वरा अपनाये गये पांचों संकल्पों का अपना अति महत्वपूर्ण स्थान है तथा इन्हीं सकंल्पों के सार्थक होने पर ही भारतीय आध्यात्मिक शक्ति, गौरवपूर्ण संस्कृति व संस्कार अभिभूत होंगे तथा भारत का सामर्थ दृष्टिगोचर होगा। भारत का सर्वश्रेष्ठ ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम विश्व के किसी भी धर्म से कहीं ऊंचा स्थान रखता है।

प्रधानमंत्री मोदी भी इसी ध्येय वाक्य को अपनाने में लगे हुए है। तभी भारत ने कोविड़ से जुझते विश्व के 150 देशों को वैक्सीन पंहुचायी। तालिबानी मानसिकता से ग्रस्त अफगानिस्तान को भी रसद भेजी, भारत का कभी साथ न देने वाले फिलीस्तीन को टनों राहत समाग्री वर्ष 2023 में भेजी तथा आतंकवादी हमास की 7 अक्टूबर 2023 के कृत्य की घोर निन्दा मानवता के दृष्टिकोण को अपनाते हुए कीं। विश्व स्तर पर नरेन्द्र मोदी स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिखाई गई व अपनी बनायी गई राह पर ही अग्रसित होते है। स्वंय पर विश्वास ही उनका एक मात्र सहारा है। मोदी चाहते है कि भारत देश में व्याप्त विविधता को उल्लास के साथ अपनाना चाहिए। यही विविधिता ही देश की बहुत बड़ी ताकत साबित होगी। भारत का प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र में अपने मात्र अधिकार की ही मांग न करें अपितू राष्ट्र के प्रति उसके स्वंय के कर्तव्य का भी प्रदर्शन करे। प्रत्येक नागरिक को यह भी आभास होना चाहिए कि वे राष्ट्र को दे क्या रहा है? वह राष्ट्र से मात्र कुछ न कुछ लेने के लिए ही उत्सुक नहीं रहे।

स्वामी विवेकानंद भारतीय धर्म, अध्यात्म एवं दर्शन के सच्चे ध्वज वाहक थे। विवेकानंद का जीवन दर्शन संपूर्ण विश्व के लिए शांति, प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता तथा शक्ति से ओत प्रोत था। वे सदैव लक्ष्मीनारायण भगवान से पहले दरिद्र नारायण की सेवा के प्रबल पक्षधर थे। स्वामी जी का अमेरिका के शिकागों में धर्म संसद में दिया गया उनका भाषण आज भी सारगर्भित व प्रासंगिक है तथा पूर्ण श्रद्धा व आदर से याद किया जाता है। वर्तमान में विवेकानंद युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन गए है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को पूरजोर तरीके से अपनाया व स्थापित करते हुए कहा था कि विश्व के सभी धर्मों का समान आदर व सत्कार करना चाहिए। उनका मानना था कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। अतः भारतीय युवा वर्ग को देश के प्रति सदैव निर्माण की सोच कायम करनी ही होगी। तभी भारत की प्रगति व विकास संभव हो सकेगा।❑❑

डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर 251001 (उ.प्र.), के वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष व ऐसोसियेट प्रोफेसर के पद से व महाविद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं तथा स्वतंत्र लेखक व टिप्पणीकार है।

नलकूपों से भी बढ़ रहा है जल संकट

संयुक्त राष्ट्र के विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित अंतर संबंध आपदा संकट रिपोर्ट 2023 में कहा गया है कि सिंधु और गंगा के इलाकों में भूजल का स्तर खतरनाक बिंदु पर पहुंच गया है। पंजाब के 80 प्रतिशत क्षेत्र अति दोहन का शिकार है और इसके चलते उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भू–जल का गंभीर संकट पैदा होने की संभावना है। भारत का यही वह क्षेत्र है, जहां सबसे ज्यादा धान, गेहूं और दालों का उत्पादन होता है। स्पष्ट है कि इन क्षेत्रों में अगर भू–जल तेजी से घट जाएगा, तो खाद्यान्न उत्पादन भी बुरी तरह प्रभावित होगा। यह स्थिति भूख, बेरोजगारी और उद्योगों के लिए बड़े संकट का कारण बन सकती है।

जिस तेज रफ्तार के साथ कृत्रिम, भौतिक और उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है, उतनी ही तेज गति से प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हुआ और उनकी उपलब्धता लगातार घटती ही जा रही है। ऐसे प्राकृतिक संसाधनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, पानी। जल ही जीवन है की वास्तविकता से अवगत होने के बावजूद पानी की उपलब्धता भूमि के नीचे और ऊपर निरंतर कम होती जा रही है। फलस्वरुप भारत तेजी से भूजल की कमी के चरम बिंदु की ओर बढ़ रहा है। देश के कई इलाके पहले से ही इस मोर्चे पर चिंताजनक स्थिति का सामना कर रहे हैं। वहीं कुछ अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि 2025 तक इसका असर अन्य इलाकों में भी दिखना शुरू हो जाएगा। यह संकट पेयजल और खाद्यान्न दोनों की उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है।

भू–जल दोहन के आसान तरीकों में नलकूप है, जो घरों व गलियों से लेकर खेतों के लिए पानी खींच रहे हैं। नलकूप की सुविधा मिलने के बाद बहुत सारे किस्म की बेमौसम की फसलें लोग बोने लगे हैं जिनमें से कई फसलों के लिए अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। धान की फसल भी उनमें से एक है। हालांकि पंजाब और हरियाणा की सरकारें किसानों से लगातार अपील करती रही हैं कि वह वर्षा से पहले धान की खेती न करें और भू–जल दोहन को नियंत्रित रखें। जल के अतिरिक्त दोहन के लिए दंड के प्रावधान भी किए गए हैं। जब इसका असर नहीं दिखा, तो किसानों को प्रोत्साहन राशि की घोषणा भी की गई, लेकिन परिणाम 'ढाक के तीन पात' ही रहे।

जरूरी है कि अंधाधुंध नलकूपों की गहरी खुदाई पर तत्काल नियंत्रण लगाकर इसके वैकल्पिक उपाय तलाशे जाने चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में जल संकट कई गुना अधिक रफ्तार से बढ़ेगा।– **डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा**

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जमीन से खींचे जाने वाले 70 प्रतिशत जल का उपयोग खेती किसानी के लिए ही होता है। दुनिया की 6 पर्यावरणीय प्रणालियां जल का स्तर नीचे गिरने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते संकट के चरम बिंदु पर है। अगर हालात नहीं बदले तो जीव–जंतु विलुप्त होंगे, भूजल घटेगा, हिमखंड पिघलेंगे और असहनीय गर्मी पड़ेगी। प्राकृतिक संपदा का दोहन और उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप विनाशकारी बदलाव ला सकते हैं। इसका परिस्थितिकी तंत्र, जलवायु पद्धति और समग्र पर्यावरण पर गंभीर असर दिखेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में पहले से ही भूजल अधिकतम निचले स्तर पर है। अब भारत भी उन देशों में शामिल हो सकता है, जो जल्दी ही इस चरम बिंदु की सीमा लांघ सकते हैं।

भारत दुनिया में सबसे अधिक भू–जल का प्रयोग करता है। अमेरिका और चीन दोनों देशों के कुल प्रयोग से भारत का भूजल प्रयोग अधिक है। भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका देश की खाद्य जरूरत को पूरा करने के लिए आज से महत्वपूर्ण है लेकिन यहां तेजी से भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है। आजादी के समय तक प्रति व्यक्ति सालाना दर के हिसाब से पानी की उपलब्धता 6000 घन मीटर थी जो अब घटकर डेढ़ हजार घन मीटर रह गई है। जिस तेजी से पानी के इस्तेमाल के लिए दबाव बढ़ रहा है और जिस बेरहमी से भूमि के नीचे के जल का दोहन नलकूपों से किया जा रहा है उसे यह निश्चित हो चला है कि अगले कुछ साल बाद जल की उपलब्धता घटकर 1600 की जगह 1100 घन मीटर ही रह पाएगी। टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि भूमिगत जल के आवश्यकता से अधिक प्रयोग से भावी पीढ़ी को कालांतर में जबरदस्त जल संकट का सामना करना पड़ेगा नलकूपों

अमेरिका और चीन दोनों देशों के कुल प्रयोग से भारत का भूजल प्रयोग अधिक है। भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका देश की खाद्य जरूरत को पूरा करने के लिए आज से महत्वपूर्ण है लेकिन यहां तेजी से भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है।

के उत्खनन संबंधी जिन आंकड़ों को हमने क्रांति की संज्ञा दी थी दरअसल वहीं तबाही की पूर्व सूचना थी, जिसे हम नजर अंदाज करते चले आ रहे हैं।

यह ठीक है कि आजादी के अमृत वर्ष आते–आते देश में खाद्यान्न सुलभता सुनिश्चित हुई है लेकिन इसके लिए जी हरित क्रांति प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है उसके कारण नलकूपों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है, फलस्वरुप उतनी ही तेजी से भूमिगत जल की उपलब्धता भी घटी है। केंद्रीय भू–जल बोर्ड के अनुसार नलकूप खुदाई की आमतौर पर प्रचलित तकनीक गलत है। इसके लिए जमीन के भीतर 30 मीटर तक विधिवत पाबंदी होनी चाहिए ताकि जमीन की इस गहराई वाले हिस्से का पानी अपने क्षेत्र में सुरक्षित रहे। इसके बाद नीचे की खुदाई जारी रखनी चाहिए। यह तकनीक अपनाने से खर्चे में 30,000 रू. की वृद्धि जरूर होती है लेकिन भूजल स्तर में गिरावट नहीं आती।

एक अध्ययन के अनुसार 1947 में देश में 1000 के करीब नलकूप थे जिनकी संख्या बढ़कर अब कई करोड़ हो गई है। सस्ती या मुफ्त बिजली देने से नलकूपों की संख्या में और भी वृद्धि हुई। पंजाब और मध्य प्रदेश की सरकारों ने किसानों को मुफ्त बिजली देकर नलकूप खनन को बेवजह प्रोत्साहित किया है। पंजाब के 12 हरियाणा के तीन और मध्य प्रदेश के 15 जिलों में पानी ज्यादा निकाला जा रहा है जबकि वर्षा जल से उसकी भरपाई ना के बराबर है। गुजरात के मेहसाणा और तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिलों में तो भूमिगत जल लगभग खत्म ही हो गया है। जल स्तर नीचे जाने से पानी खींचने में ज्यादा बिजली खर्च हो रही है। जिन क्षेत्रों में पानी का अत्यधिक दोहन हो चुका है वहां पानी खींचने के खर्चे में 5000 करोड रुपए का इजाफा हुआ है। नलकूपों के बड़ी मात्रा में खनन से जमीन और कुओं के जल स्तर पर जबरदस्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हालत यह है कि 75 प्रतिशत कुंआ हर वर्ष दिसंबर माह में 10 फीसद जनवरी में और 10 प्रतिशत अप्रैल में सुख जाते हैं। एक नलकूप 5 से 10 कुओं का पानी सोख लेता है। जल विशेषज्ञ और पर्यावरणविद् मानने लगे हैं कि जल स्तर को नष्ट करने में और जल धाराओं की गति अवरुद्ध करने में नलकूपों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों का इस बारे में कहना है की भूमि में 210 से लेकर 300 फीट तक छेद कर देने से धरती की परतों में बह रही जलधाराएं नीचे चली जाती है, जिसके चलते जल स्तर भी नीचे चला जाता है।

ऐसे में जरूरी है कि अंधाधुंध नलकूपों की गहरी खुदाई पर तत्काल नियंत्रण लगाकर इसके वैकल्पिक उपाय तलाशे जाने चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में जल संकट कई गुना अधिक रफ्तार से बढ़ेगा। इस समस्या का समाधान बड़ी मात्रा में पारंपरिक जल ग्रहण क्षेत्र तैयार करना है। पारंपरिक मानते हुए जलग्रहण की तकनीक की हमने पूर्व में घोर उपेक्षा की है, जिसका खामियाजा देश के कई हिस्सों में लोग उठा रहे हैं। हमें पुरानी पारंपरिक और स्वदेशी तकनीक से जल भंडारण की दिशा में अब ठोस पहल करने की जरूरत है। ❑❑

रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में कटौती के बारे में सोचना चाहिए

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक 8 दिसम्बर 2023 को समाप्त हुई और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने नीतिगत रेपो दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करते हुए इसे 6.50 प्रतिशत पर यथावत बनाए रखा है, क्योंकि मुख्य रूप से भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति की दर नियंत्रण में बनी हुई है। हालांकि अभी यह देश के मध्यावधि लक्ष्य 4 प्रतिशत के अंदर नहीं आई है। परंतु, भारतीय अर्थव्यवस्था जिस गति से आगे बढ़ रही है, इसे देखते हुए एवं आर्थिक विकास की दर को और अधिक गति देने के उद्देश्य से अब भारत में ब्याज दरों को कम किये जाने का समय आ गया लगता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति की दर का 4 प्रतिशत से अधिक बने रहने के पीछे मुख्य कारण तेल एवं खाद्य पदार्थों (फल, सब्जी, आदि) में अचानक वृद्धि होते रहना है। अन्यथा, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति की दर तो लम्बे समय से रिणात्मक बनी हुए है एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मूल मुद्रा स्फीति की दर भी पूर्ण रूप से नियंत्रण में है।

हां, वैश्विक स्तर पर आर्थिक परिस्थितियां जरूर भारत में ब्याज दरों को कम करने के पक्ष में नजर नहीं आ रही हैं। चीन सहित, विश्व के कई देशों में आर्थिक विकास दर कम हो रही है एवं इन देशों में मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से ब्याज दरों को अभी भी ऊंची दरों पर बनाए रखा गया है। इसी माह अमेरिका में सम्पन्न हुई फेडरल रिजर्व की बैठक में फेड रेट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। चूंकि अन्य देशों में ब्याज की उच्च दर अभी भी बनी हुई है अतः अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए पर दबाव बना हुआ है। इन परिस्थितियों के बीच यदि भारतीय रिजर्व बैंक भारत में ब्याज दरों को कम करता है तो भारतीय रुपए पर दबाव और अधिक बढ़ेगा। अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों में मुद्रा स्फीति की दर में सुधार जरूर दृष्टिगोचर है। अमेरिका में तो अभी हाल ही में सोवरेन बांड प्रतिफल में गिरावट भी दर्ज हुई है एवं अमेरिकी डॉलर की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार

अब भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मूल मुद्रा स्फीति की दर अब नियंत्रण में है इसलिए आगामी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में ब्याज दरों को कम करने के संबंध में विचार किया जाना चाहिए।

– स्वदेशी संवाद

में कुछ कम हुई है। इससे कई देशों के पूंजी (शेयर) बाजार मजबूत हुए हैं। अतः अब आगे आने वाले समय में इन परिस्थितियों के बीच विश्व के विभिन्न देशों द्वारा ब्याज दरों में कमी किए जाने की संभावना बढ़ती जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को तो इससे अत्यधिक लाभ होगा। ब्याज दरें कम होने से भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित किए जाने वाले उत्पादों की उत्पादन लागत कम होगी और भारत में निर्मित होने वाले उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे, इससे इन उत्पादों का भारत से निर्यात बढ़ेगा।

भारत में आंतरिक आर्थिक परिस्थितियां लगातार अनुकूल बनी हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 की प्रथम तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने के बाद द्वितीय तिमाही में भी 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की गई है। यह वृद्धि दर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थानों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमानों से कहीं अधिक है। भारत में लगातार बढ़ रहे निवेश एवं केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे पूंजीगत एवं अन्य खर्च में अपार वृद्धि के चलते सम्भव हो पा रहा है। विनिर्माण एवं निर्माण गतिविधियों में अतुलनीय वृद्धि के चलते दूसरी तिमाही में विकास दर अत्यंत आकर्षक रही है। आगे आने समय में भी विनिर्माण गतिविधियों में मजबूती, निर्माण में भारी वृद्धि एवं ग्रामीण इलाकों में बढ़ रही उत्पादों की मांग के चलते घरेलू स्तर पर उत्पादों की मांग में और अधिक सुधार होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमानों में सुधार करते हुए इसे 7 प्रतिशत तक पहुंचा दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति की दर

भारतीय रिजर्व बैंक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति की दर को नियंत्रण में करना चाहता है। जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति की इस दर में विभिन्न खाद्य पदार्थों की कीमतें भी शामिल रहती हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतें पूर्णतः मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत पर तय होती हैं।

को नियंत्रण में करना चाहता है। जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति की इस दर में विभिन्न खाद्य पदार्थों की कीमतें भी शामिल रहती हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतें पूर्णतः मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत पर तय होती हैं। जब किसी वर्ष किसी खाद्य पदार्थ की फसल संतोषजनक होती है तो उस खाद्य पदार्थ की कीमतें नियंत्रण में रहती है और यदि किसी मौसम में किसी सब्जी अथवा फल की फसल ठीक नहीं रहती है तो उसकी कीमतें बाजार में आसमान छूने लगती हैं। जैसा कि अक्सर भारत में प्याज, टमाटर एवं अन्य सब्जियों एवं फलों की स्थिति में देखा गया है। इस प्रकार की मुद्रा स्फीति को ब्याज दरों में वृद्धि कर नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इन पदार्थों की कीमतों को तो केवल इनकी आपूर्ति को बढ़ाकर ही नियंत्रण में लाया जा सकता है। फिर, इन पदार्थों की बढ़ती कीमतों के चलते यदि ब्याज दरों में वृद्धि हो रही है तो यह अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, के लिए हानिकारक परिणाम देता दिखाई दे रहा है। इन कारणों के चलते अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मूल मुद्रा स्फीति की दर को ही नियंत्रित करना चाहिए एवं उसके आधार पर ही ब्याज दरों में वृद्धि अथवा कमी की जानी चाहिए। जब फल एवं सब्जियों की कीमतों में अचानक हो रही वृद्धि को ब्याज दरें बढ़ाकर नियंत्रित ही नहीं किया जा सकता है तो फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इन मदों को शामिल ही क्यों रखा जाना चाहिए।

अतः कुल मिलाकर अब भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मूल मुद्रा स्फीति की दर अब नियंत्रण में है इसलिए आगामी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में ब्याज दरों को कम करने के संबंध में विचार किया जाना चाहिए।❑❑

कुदरत से खिलवाड़ के फलितार्थ

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनडीपी) की ओर से ताजा–ताजा आई एमिशन गैप रिपोर्ट दुनिया के सभी देशों के लिए चेतावनी है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि यदि सभी देश पेरिस समझौते के वादों को पूरा नहीं करते हैं तो इस सदी के अंत तक दुनिया 2.5 डिग्री से बढ़कर 2.9 डिग्री तक गर्म हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया का तापमान नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। इस साल अक्टूबर तक 86 दिन ऐसे रहे, जब दुनिया का तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक था। इसी साल का सितंबर महीना अब तक का सबसे गर्म महीना घोषित किया गया। सितंबर में तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक रहा था। वर्ष 2021 से जुलाई 2023 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1.3 प्रतिशत का इजाफा हुआ जो 59.4 गीगाटन कार्बन डाईऑक्साइड के बराबर है।

जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर में हलचल है। मानों प्रकृति अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार से अब अकुलाने लगी है। जिन इलाकों में सुखे का लंबा इतिहास रहा है, उन इलाकों में अब बाढ़ के मंजर दिखाई देने लगे हैं। जिन इलाकों में कभी भारी बारिश हुआ करती थी, वे इलाके बारिश के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। स्थिति का अनुमान जैसलमेर शहर से लगाया जा सकता है। जैसलमेर राजस्थान का वह इलाका है जहां पानी की उपलब्धता सबसे कम हुआ करती थी। इस इलाके में बारिश का इतिहास भी काफी सीमित और नपा तुला ही रहा है। लेकिन दो साल पहले जैसलमेर में भारी बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ का मंजर देखकर लोगों के कान खड़े हो गए थे। बाढ़ के उफान में बड़ी–बड़ी गाड़ियां बहती नजर आई थी। जैसलमेर में यह सब तब हो रहा था जब बरसात के लिए भारत में मशहूर चेरापूंजी का इलाका बारिश के लिए बादलों की ओर टकटकी लगाए था। जब भारत की जमीन पर इस तरह की प्राकृतिक अनहोनी हो रही थी, ठीक उसी समय सदैव 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले रूस के याकुतश्क शहर का तापमान अचानक बढ़कर 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में 54.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था, जबकि उससे बहुत ठंडा समझे जाने वाले शहर लॉस वेगास का पारा 48 डिग्री के पार चला गया था। इसी समयावधि में जर्मनी में हुई लगातार बारिश ने पिछली सदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस तरह की उलट–पुलट की घटनाएं स्पष्ट संकेत दे रही है कि कुदरत के मिजाज ठीक नहीं है।

क्या यह सही समय नहीं है कि पेरिस समझौते को लागू करने के लिए वैश्विक दबाव बढ़ाने के साथ–साथ हम परिवेश और प्रकृति के प्रति अपने व्यवहार की समीक्षा करें और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के स्थान पर उन विकल्पों पर भी विचार करें जो समूची मानवता को लोभ, स्वार्थ और हम बड़े के दम्भ से दूर एक खुशहाल जीवन का आश्वासन दे।

–शिवनंदन लाल

सारी दुनिया में सामान्य तापमान बढ़ रहा है। वैज्ञानिक भाषा में इसे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान का बढ़ना कहा जाता है। इसके खतरों से वैज्ञानिक और पर्यावरणविद् लगातार आगाह कर रहे हैं, लेकिन कथित विकास की व्यग्रता में दुनिया उन तथ्यों को भी नजरअंदाज कर रही है जो समूची मानव सभ्यता के लिए किसी बड़े खतरे की प्रस्तावना की तरह है। बार–बार आने वाले समुद्री तूफान, चक्रवात, हिमनदों का फटना, सतत भूस्खलन, कहीं भीषण गर्मी तो कहीं भीषण सर्दी, लगातार बारिश, लगातार भूकंप और दुनिया के अलग–अलग हिस्सों में जंगलों का धधकना इस बात की ओर इशारा करता है कि जलवायु के आंगन में गहरी उथल–पुथल है, और इसे मनुष्य यह सोचकर अनदेखा नहीं कर सकता कि किसी और के आंगन में आग से हमें क्या लेना देना? जब दुनिया के किसी भी हिस्से में बड़ी पर्यावरणीय हलचल होती है तो वह समूचे मानव समुदाय के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए, क्योंकि

यदि जंगल में किसी एक पेड़ में लगी आग को बाकी पेड़ यह सोचकर अनदेखा करेंगे कि उन्हें इससे क्या, तो सारा जंगल आग के आतप और आतंक से बहुत देर तक नहीं बच सकेगा।

विकास के नाम पर हमने जिस जीवन शैली को अपनाया है उसके चलते वातावरण में लगातार विषैली गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। पराबैंगनी किरणों को हम तक पहुंचने से रोकने वाली ओजोन परत कमजोर पड़ने की चिंता जानकारों को लगातार परेशान कर रही है। दूसरी तरफ पर्यावरण में एअरोसाल की बढ़ती हुई मात्रा पृथ्वी के जल चक्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। एअरोसाल, गैस के साथ ठोस कणों या बूंदों के मिश्रित होने की स्थिति को कहते हैं और इसकी अत्यधिक मात्रा के कारण मानसून का व्यवहार भी अनियमित हो गया है।

मानसून का चाल–ढाल भी बदल गया है। इस साल अक्टूबर महीने में अचानक मानसून की सक्रियता बढ़ गई। 10 से 15 अक्टूबर के बीच देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। विक्रमी संवत के अनुसार यह आश्विन माह का शुक्ल पक्ष होता है। मानसून की असमय सक्रियता से अचानक सर्दी के आने की आशंका पैदा हुई। लोकमान्यताएं भी कहती हैं कि जब भी मानसून अनियमित व्यवहार करता है तो जीवन को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना ही होता है। इस साल तो मौसम में इतने उलट फेर हुए की तमाम मौसम वैज्ञानिकों ने इस साल के मौसम को रिकॉर्ड तोड़ने वाला मौसम तक कह दिया। इससे पहले नासा की एक रिपोर्ट में वर्ष 2020 को सबसे गर्म साल बताया गया था। इससे भी पहले अप्रैल 2017 में क्लाइमेट सेंटर नाम के अंतरराष्ट्रीय संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पिछले 628 महीना में से कोई भी महीना उतना ठंडा नहीं रहा जितना पूर्ववर्ती वर्ष में वह महीना रहा करता था। यानी पृथ्वी के आसपास

का तापमान लगातार बढ़ता रहा। अब यूएनईपी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया के देश पेरिस समझौते पर काम नहीं करते है तो सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है।

इसी साल जी–20 की बैठक के दौरान बढ़ते वैश्विक तापमान को लेकर जारी किए गए परिपत्र में कहा गया कि तापमान में वृद्धि के कारण पहले से ही मानव और प्राकृतिक प्रणाली में बड़ा बदलाव हो रहा है। इस बदलाव को हिमनदों की मौजूदा स्थिति से भी आंका जा सकता है। पिछले दिनों एक अध्ययन में यह बात सामने आई की सन 2000 के बाद हर साल 280 अरब टन हिमनद गायब हुए हैं। हिमनदों का गायब होना वस्तुतः उनका पिघलने ही है। दुनिया भर में समुद्रों में पानी की जो बढ़ती मात्रा पर्यावरणविदों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, उसमें 21 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पिघलते हुए हिमनदों का ही है। हिमनदों का पिघलना पहाड़ी आबादी के लिए परेशानी का भी सबब है। हिमनदों के पिघलने से पहाड़ी क्षेत्रों में झील बन जाती है और जब वह झील फटती है तो इलाके में तबाही मचा देती है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट लगातार गर्म हो रही है और गर्मी के कारण उसके आसपास के हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं।

इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहें या वैश्विक तापमान का बढ़ना कहें या कोई और नाम दे, लेकिन सच तो यही है कि प्रकृति का आधिकारिक दोहन करने की हमारी नीतियों और मानसिकता ने समूची मानव जाति को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां हम सबको प्रकृति और मनुष्य की आत्मीयता के समीकरण को फिर से साधना ही होगा। भारतीय संस्कृति में शायद इसीलिए कभी देवताओं के रूप में तो कभी परंपराओं के तौर पर प्राकृतिक शक्तियों की सामर्थ्य को नमन किया जाता रहा है।

दुनिया के देशों ने पेरिस समझौते के तहत क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए वैश्विक गैस का कम से कम उत्सर्जन करने का वादा किया है। छोटे देशों पर इसके लिए दबाव भी बढ़ाया जा रहा है और कई एक विकासशील देश इस दिशा में ठोस कार्य नीति के साथ आगे भी आ रहे हैं, लेकिन बड़े और विकसित देश लगातार अंगूठा दिखा रहे हैं।

ऐसे में, क्या यह सही समय नहीं है कि पेरिस समझौते को लागू करने के लिए वैश्विक दबाव बढ़ाने के साथ–साथ हम परिवेश और प्रकृति के प्रति अपने व्यवहार की समीक्षा करें और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के स्थान पर उन विकल्पों पर भी विचार करें जो समूची मानवता को लोभ, स्वार्थ और हम बड़े के दम्भ से दूर एक खुशहाल जीवन का आश्वासन दे। ❑❑

आत्मनिर्भर भारत नेहरु के मॉडल से अलगः डॉ. अश्वनी महाजन

लैपटॉप आयात प्रतिबंध की बहस के बीच स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा संपादित एक नई किताब में तर्क दिया गया है कि मोदी सरकार का 'आत्मनिर्भरता' दृष्टिकोण नेहरूवादी दृष्टिकोण से मौलिक रूप से अलग है, जिसने विकास को धीमा कर दिया है। उनका तर्क है कि कई लोगों को डर था कि वर्तमान सरकार का 2020 का आत्मनिर्भर कदम नेहरूवादी युग के लाइसेंस राज की वापसी होगी, अब यह स्पष्ट है कि पूर्व रणनीतिक रूप से तैनात है और स्पष्ट रूप से सोचा गया है। उनका मानना है कि जहां नेहरूवादी दृष्टिकोण का उद्देश्य 'प्रतिबंधात्मक उपायों के माध्यम से आत्मनिर्भरता' निजी क्षेत्र को रोकना और अनुसंधान एवं विकास का 'गला घोंटना' और विकास को धीमा करना था, वहीं मोदी सरकार का मिशन 'आत्मनिर्भर भारत' अनुचित प्रथाओं से सुरक्षा के साथ–साथ घरेलू दक्षता को प्रोत्साहित करना चाहता है।

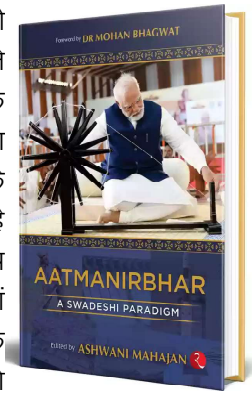

महाजन लिखते हैं, "यह सब दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता लाने के बारे में है। यह एक नीति है जिसका उद्देश्य उन चीजों का उत्पादन करना है जो वर्तमान में आयात की जा रही हैं, और इस प्रक्रिया में दुनिया के लिए उत्पादन करने की क्षमता का निर्माण करना है।" महाजन ने नेहरूवादी आत्मनिर्भरता मॉडल पर एक प्रस्तावना में लिखा है, "इन प्रतिबंधात्मक नीतियों के कारण विकास की कम दर को शरारतपूर्ण ढंग से 'हिंदू विकास दर' कहा गया, जिसे 'नेहरूवादी विकास दर' कहा जाना चाहिए।" पुस्तक 'आत्मनिर्भर–एक स्वदेशी प्रतिमान'। पुस्तक की प्रस्तावना में मोहन भागवत ने प्रगति पर पश्चिमी विमर्श के 'भौतिकवादी, खंडित और उपभोक्तावादी दृष्टिकोण' को बदलने के लिए आत्मनिर्भरता केंद्रित विकास पर 'भारतीय दृष्टि' का आह्वान किया है।

यह पुस्तक अर्थशास्त्री प्रोफेसर अशोक कुमार लाहिड़ी से लेकर भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेश्वरन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, पीएम के आर्थिक आयोग के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय सलाहकार परिषद, सदस्य पीएम–ईएसी संजीव सान्याल और शमिका रवि और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार जैसे लोगों के आत्मनिर्भर भारत पर 18 निबंधों का संकलन है। विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) के महानिदेशक, सचिन चतुर्वेदी का मानना है कि वर्तमान दृष्टिकोण विशिष्ट है क्योंकि यह 'टैरिफ और गैर–टैरिफ उपायों के विवेकपूर्ण मिश्रण' का उपयोग करते हुए उद्योग को अनुचित प्रतिस्पर्धा से भी बचाता है। मुक्त व्यापार समझौतों से इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च की प्रोफेसर एमेरिटस आशिमा गोयल सहमत हैं और मोदी सरकार के आत्मनिर्भरता मॉडल को 'निर्यात प्रतिस्पर्धा' की संज्ञा देती हैं, जो विनिर्माण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन अनुचित प्रतिस्पर्धा से भी बचाती है ताकि पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं घरेलू स्तर पर विकसित हो सकें। दूसरी ओर, अशोक लाहिड़ी ने भारतीय उद्योग की 'प्रतिस्पर्धा की कमी के मूल कारणों' की ओर इशारा किया है, जिन्हें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है– लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे की कमी, कृषि और घरों के लिए बिजली सब्सिडी की उच्च लागत, भूमि अधिग्रहण की समस्याएं, उच्च रेलवे माल ढुलाई लागत, श्रम बाजारों में लचीलापन और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की अनुपस्थिति। पीएम–ईएसी की सदस्य शमिका रवि ने माना है कि नया आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण निरंकुश नहीं है और जबकि बाजार दक्षता और निजीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, धन की एकाग्रता और असमानता को बनाए रखने से रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय और सामाजिक सुरक्षा जाल सुनिश्चित किए जाने चाहिए। वह खाद्य, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में अधिक आत्मनिर्भरता और घरेलू विकास के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता का आह्वान करती हैं। राजीव कुमार आयातित तेल पर निर्भरता कम करने के लिए गैर–जीवाश्म ऊर्जा में आत्मनिर्भरता का आह्वान करते हैं, जबकि सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज के प्रोफेसर अभिजीत दास का नया दृष्टिकोण 'अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए रणनीतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग करना' है। वह कनाडा और यूरोपीय संघ के एफटीए में कुछ 'कठिन दायित्वों' पर भी आगाह करते हैं जो भारत की आत्मनिर्भरता के संकल्प के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

https://ashwanimahajan.wordpress.com/2023/11/26/

शहीद बाबू गेनू जी के बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि

नदेसर स्थित स्वदेशी जागरण मंच के काशी प्रांत कार्यालय में स्वदेशी आंदोलन में प्रथम शहीद बाबू गेनू जी के बलिदान दिवस पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। पहले सभा के द्वारा श्रद्धांजलि देने के बाद बाबू गेनू जी के जीवन के बारे में बताया कि कैसे 1908 में महाराष्ट्र के छोटे से गांव में जन्मे एक

बालक ने राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित होकर मात्र 22 वर्ष की आयु में अपना बलिदान दे दिया। हमें अपने शहीदों के बलिदानों से यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। हमें इन शहीदों की बलिदानों को समय–समय पर याद करना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को भी शहीदों की महान गाथा पता चले। कार्यक्रम में स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।

काशी महानगर के रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्घाटन स्वदेशी जागरण मंच के वरिष्ठ प्रचारक श्री बलराज सिंह ने किया। कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक सत्येन्द्र सिंह, काशी विभाग के पूर्णकालिक अमरेंद्र सिंह, सोनभद्र के पूर्णाकालिक अजीत, भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष उमाकांत, कृषि वैज्ञानिक आनंद प्रकाश, प्रांत प्रमुख सक्षम विजय, कार्यालय प्रमुख अखिलानंद, भाजपा कार्यकर्ता निशा, सह संयोजक मंच नवीन, नीरज, अक्षय की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संयोजन मंच की महानगर संयोजिका कविता मालवीय ने किया।

https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2023/12/12/Tribute-paid-to-martyr-Babu-Genu-ji-on-his-martyrdom-day.php

युवाओं को उद्यमी बनाने का किया जाएगा कार्यः दुबोलिया

स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय बैठक सरस्वती शिशु मन्दिर पेंड्रा में हुई। इसमें क्षेत्रीय संगठन मंत्री केशव दुबोलिया ने बताया कि स्वावलंबी भारत अभियान की कड़ी में युवाओं को उद्यमी बनाने का कार्य किया जाएगा।

उन्होंने कहा युवाओं नौकरी तलाशने की मानसिकता को बदलकर नौकरी देने वाले उद्यम बनने की ओर अग्रसर करने का अभियान है। रोजगार सृजन केंद्र के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को उद्यमिता के विभिन्न आयामों जैसे 64 कलाओं आधारित सांस्कृतिक स्टार्टअप, सोलह सिंगार स्टार्टअप, हर्बल ब्यूटी डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स फैशन एसेसरीज मातृशक्ति उद्यमिता, 108 जड़ी–बूटी आधारित हर्बल स्टार्टअप, मोटा अनाज आधारित 1008 भारतीय व्यंजनों का रेडी टू ईट स्टार्टअप, छप्पन भोग खानपान उद्यमिता, 108 भारतीय मसाला स्टार्टअप, वनौषधि–आयुष स्टार्टअप, ट्रेडिंग, जनजातीय उद्यमिता, हथकरघा, बुटिक गारमेंट्स स्टार्टअप, हस्तशिल्प, गोबर उत्पाद, पूजन सामग्री स्टार्टअप, फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप, शिल्प एवं हथकरघा, डेयरी स्टार्टअप, बेकरी स्टार्टअप, महुआ स्टार्टअप, जैव उर्वरक, घरेलू , दैनिक उपयोग की वस्तुओं का स्टार्टअप, चमड़ा, फुटवियर, बायोप्लास्टिक, स्पोर्ट्स आइटम स्टार्टअप, घरेलू इलेक्ट्रानिक स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर मेडिकल इलेक्ट्रानिक स्टार्टअप, नेचुरोपैथी एक्युप्रेशर स्टार्टअप, संगीत एवं मनोरंजन उपकरण स्टार्टअप, रियल स्टेट सामग्री स्टार्टअप, थ्रीडी प्रिंटिंग, सौर ऊर्जा, बैटरी इलेक्ट्रिकल वाहन स्टार्टअप सहित उनके अभिरुचि के अनुसार उद्यम शुरू करने स्टार्टअप, उद्यमिता, पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित किया जा सकता है।

केशव दुबोलिया ने बताया कि प्रत्येक गांव, जिला में उपभोक्ता आधारित दैनिक आवश्यकताओं की अधिकांश वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए गांव, जिला में स्वदेशी उत्पादन, लोकल के लिए वोकल, सहकारिता आधारित आर्थिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया जा रहा है इससे स्थानीय उत्पाद प्राथमिकता की श्रेणी में आ जाएगी। प्रत्येक गांव, जिले में इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम को विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सहकारिता उद्यमिता के विश्वास को बढ़ावा देना, क्वालिटी कंट्रोल के अनुकूल माहौल तथा मार्केटिंग के स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। इससे समाज के अंतिम छोर के युवा स्वावलंबी होंगे तभी सही मायने में भारत स्वावलंबी होगा।

संयोजक सदस्य नीरज जैन ने बताया कि भारत के पास मौजूदा वक्त में 16 से 30 वर्ष के 38 करोड़ युवाशक्ति का सामर्थ्य हैं तथा प्रत्येक वर्ष सवा करोड़ युवा रोजगार के लिए बाजार में आ रहे हैं। इनके रोजगार की पूर्ति अकेले सरकार या कंपनियां नहीं कर सकती हैं। इसके लिए स्व उद्यमिता को बढ़ावा देने को ध्यान में रखकर भाजपा आगे बढ़ रही है। युवाओं में उद्यमिता, स्वरोजगार व अर्थसृजन करने को एक जनआंदोलन बनाना प्रमुख उद्देश्य है। ज्ञात हो कि इस दिशा में मोदी सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से ईज आफ डूईंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत ने प्रभावी बढ़त बना ली। आशीष गुप्ता ने बताया कि भारत सरकार की अनेक योजनाएं संचालित हो रही है, योजना के माध्यम से जिले में उधमिता स्थापित कराने का लक्ष्य है। इसके अलावा पं दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री उद्यमिता

योजना के तहत युवाओं को उद्यमिता स्थापित करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तथा वर्तमान में औद्योगिक भूमि पर्याप्त उपलब्ध है। इससे आने वाले समय में जिले के युवा औद्योगिक भूमि आबंटित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उद्यमी बनने के लिए बैंक को का अपना अपना बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें डीपीआर के आधार पर बैंक से लोन प्रदान किया जाता है। युवाओं को इसमें आगे बढ़कर बैंक से सहायता लेकर उद्यमी बनना चाहिए। इसके लिए बैंक युवाओं की सहायता के लिए सदैव तत्पर है।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से समेत विभिन्न अनुषांगिक संगठन में स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती, सहकार भारती, ग्राहक पंचायत, राष्ट्रीय सेवा भारती, भारतीय किसान संघ, भारतीय मज़दूर संघ, अखिल भारतीय विध्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग, वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय शिक्षण मंडल, विकास भारती के कार्यकर्त्ता प्रत्यक्ष तथा आभासी माध्यम से उपस्थित थे।

https://www.naidunia.com/chhattisgarh/mungeli-work-will-be-done-to-make-youth-entrepreneurs-dubolia-8252372

बेहद सादगीपूर्ण था दत्तोपंत ठेंगड़ी का जीवनः डा. राजीव कुमार

स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में एक दिया अमर बलिदानियों के नाम कार्यक्रम स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी की जयंती पर स्वतंत्रता सेनानी भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में बलिदान स्मारक के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया एवं दीपावली पर स्वदेशी उत्पाद ही खरीदने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉ. राजीव कुमार ने कार्यक्रम में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज जब कोई छोटा सा पुरस्कार पाने के लिए लोग क्या–क्या नहीं करते, वहीं एनडीए सरकार की ओर से 2002 में दिए जा रहे पद्मभूषण को ठेंगड़ी जी ने यह कहकर ठुकरा दिया कि जब तक संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार और गुरुजी को भारत रत्न नहीं मिलता, तब तक वह कोई सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे।

डॉ. राजीव ने आगे बताया कि ठेंगड़ी जी कहते थे कि किसी विचार का प्रसार या सामाजिक कार्य, बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के करना चाहिए। वास्तव में ऐसा समर्पण बड़ा दुर्लभ है। उनका जीवन सादगी पूर्ण रहा। वे एक कुशल संगठनकर्ता थे। उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच सहित कई संगठनों की स्थापना की। उनका सादगी भरा एवं संघर्षपूर्ण जीवन अनुकरणीय है। प्रांत संयोजक कपिल नारंग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के धवल दीक्षित, जिला महिला प्रमुख पूनम चौहान, प्रांत संयोजक कुलदीप सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन महानगर सह महिला प्रमुख नीलम जैन ने किया। कार्यक्रम का संयोजन प्रांत संयोजक प्रशांत शर्मा ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला संयोजक डॉ. एके अग्रवाल ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से लव सारस्वत, कशिश चौहान, नीरज सोलंकी, जयप्रकाश सक्सेना, भूदेव सिंह, डॉ. राजेश अग्रवाल, विशाल पार्षद, संतोष नारंग, नवीन चौधरी निशु, वैभव रस्तोगी आदि मौजूद रहे।

https://udaipurkiran.in/hindi/dattopant-thengadis-life-was-very-simple-dr-rajeev-kumar/

21वें इस्पातांचल स्वदेशी मेला कार्यालय का उद्घाटन

स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा आयोजित 21वां इस्पातांचल स्वदेशी मेला के निमित्त मेला कार्यालय का उद्घाटन हर्षोल्लास के साथ हुआ। मेला कार्यालय का उद्घाटन मंच के राष्ट्रीय मेला प्रमुख सचिंद्र कुमार बरियार ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मालूम हो कि जिले में विगत 23 सालों से लगतार मेला का आयोजन हो रहा है। इस बार भी स्वदेशी मेला दिनांक 11 जनवरी से 19 जनवरी 2024 तक मजदूर मैदान, सेक्टर–4, बोकारो में लगने जा रहा है। जिसका कि बोकारो के नागरिकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। स्वदेशी मेला आयोजन तैयारी हेतू स्वदेशी मेला कार्यालय–14, कौशल्या भवन, प्रथम तल, सिटी सेंटर, सेक्टर–4 रेमंड शो रूम के पीछे खोला गया है। सचिन्द्र कुमार बरियार, राष्ट्रीय मेला प्रमुख ने अपने वक्तव्य में कहा कि स्वदेशी मेला स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देती है। जिससे स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलता है। पूरे देश के छोटे–बड़े उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन स्वदेशी मेला में करते हैं और लोग जमकर खरीदारी भी करते हैं। उन्होंने मेला के सफल आयोजन की कामना भी की। उद्घाटन समारोह में अमरेंद्र कुमार सिंह, क्षेत्रीय संयोजक, दिलीप वर्मा, प्रांतीय मेला प्रमुख, कुमार संजय, जिला संयोजक, अजय कुमार सिंह, विभाग प्रमुख, प्रमोद कुमार सिन्हा, जय शंकर प्रसाद, दीपक शर्मा, सुरेश सिन्हा, उपेंद्र नारायण सिंह, अशोक रंजन, बिनोद चौधरी, अरविंद कुमार सिंह, सुजीत कुमार, मीडिया प्रभारी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहें। ❑❑

https://rnsindia.co.in/newsdetail/

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

बैठकें

सचित्र झलक

महसाना, गुजरात

पटना, बिहार

कोट्टयम, केरल

कुरुक्षेत्र, हरियाणा

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 दिसंबर 2023
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

बैठकें

सचित्र झलक

अहमदाबाद, गुजरात

गांधी नगर, गुजरात

चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, पंजाब

मनाली, हिमाचल प्रदेश

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती